www.hindmatamirror.com ● वर्ष: 12 ● अंक: 267 ● ठाणे, बुधवार 1 जुलाई, 2026 ● पेज: 8 ● मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

RNI. NO. MAHHIN/2011/43060

कैसा अजीब सा हीरो है, इसे कहां से लाए हो: काजोल

पेज 8

दैनिक हिंदमाता मिरर ठाणे

पैनी नजर, पुख्ता खबर

मुंबई छोड़ बेंगलुरु पहुंचे हार्दिक पांड्या

पेज 8

सुप्रभात

कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है, दे दो, वह तुम्हारे पास लैटकर आएगा, पर अभी उसकी बात मत सोचो। - **विवेकानंद**

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (1 जुलाई) 7:20 बजे, सूर्योदय (2 जुलाई) 6:05 बजे, **तापमान: 27 डिग्री से. (गरज के साथ बौछार।)**

शॉर्ट स्टोरी

राजीव कुमार बने एचडीएफसी चेयरमैन

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने नए पार्ट-टाइम चेयरमैन के नाम पर मुहर लगा दी है। बैंक के बोर्ड ने 66 साल के राजीव कुमार को तीन साल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावी होगी। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। अब राजीव कुमार बैंक के बोर्ड की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को तीन साल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

मुकदमे की पूर्व मंजूरी के 511 मामले लंबित

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि 31 मई, 2026 तक राज्य सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगने वाले 511 प्रस्ताव अलग-अलग प्रशासनिक विभागों के पास लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेश बकाने के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि लंबित प्रस्तावों में से 111 प्रस्ताव 90 दिनों से कम समय से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, जबकि 400 प्रस्ताव 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 111 मामले पुलिस और गृह विभाग के पास लंबित हैं। राजस्व और वन विभाग के समक्ष 66 मामले लंबित हैं।

एआई यूज के लिए एसओपी समिति बनेगी!

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल के लिए एसओपी तैयार करने की खातिर 30 दिनों के भीतर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी। हालांकि विपक्षी विधायकों ने उनकी सहमति के बिना विधान भवन में लगाए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पर आपत्ति जताई। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया है कि एआई के इस्तेमाल के संबंध में क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर एक समिति के जरिए एसओपी तैयार की जाए। समिति 30 दिन के भीतर बनाई जाएगी और उम्मीद है कि वह चार से छह महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

मुंबई में बढ़ती मांग के कारण बिजली कटौती

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि मुंबई में बार-बार बिजली कटौती की समस्या बढ़ती मांग और अतिभारित विद्युत वितरण नेटवर्क की वजह से है। स्थिति को सुधारने के लिए नए सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस समस्या को लेकर बेस्ट के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने घोषणा की कि एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि बिजली की सबसे अधिक मांग वर्ष 2025 के स्तर 907 मेगावाट से बढ़कर करीब 1010 मेगावाट तक पहुंच गई, जिसके दबाव से बार-बार बिजली आपूर्ति में रुकावटें आईं।

चेंबूर में स्कूल वैन पर गिरा बड़ा पेड

एक छात्र की मौत, 4 बच्चे घायल

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोड नंबर-11 पर यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही एक स्कूल बस पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में 10 वर्षीय एक छात्र की मौत हो गई, जबकि चार अन्य छात्र घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब 2:50 बजे हुआ। अचानक सड़क किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ बस पर गिर पड़ा, जिससे बस का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय बस में कुल 18 छात्र सवार थे। बीएमसी मुंबई वेस्ट वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना में 10 साल के एक छात्र की मौत हो गई। बस में सवार 18 छात्रों में से 12 को बचा लिया गया, एक छात्र अंदर फंसा हुआ था और बाकी छात्रों को जेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल, 10 वाहन क्षतिग्रस्त

ठाणे शहर में मंगलवार को एक बड़ा पेड़ गिर जाने से 52 वर्षीय एक व्यक्ति घायल हो गया और 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना वागले एस्टेट इलाके में सुबह करीब पौने नौ बजे हुई। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि पीड़ित पवन झा पैदल अपने कार्यालय जा रहे थे, तभी उन पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में उनके सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। तड़वी ने बताया कि उनका एक स्थानीय अस्पताल में उपचार हो रहा है। इस घटना में सड़क किनारे खड़े कम से कम 10 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

बारिश में डूबी नवी मुंबई, सड़कें बनी दरिया

नवी मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार सुबह तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ और पानी में डूबी सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगीं। तुर्भे इलाके में रेजिडेंशियल सोसाइटियों की पार्किंग में बारिश का पानी भर गया। भारी बारिश के कारण सानपाड़ा इलाके से एपीएमसी रोड तक पानी भर गया। इस रोड पर करीब डेढ़ फीट तक पानी जमा होने से लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि नालियों की सफाई ठीक से न होने की वजह से पानी तेजी से नहीं निकल पाया और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। लोगों का कहना है कि एनएमएमसी प्रशासन समय पर नालियां साफ नहीं करवाता, जिसकी वजह से हर बारिश में यही हाल होता है। पार्किंग, घरों के आसपास और मुख्य सड़कों पर पानी भरने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है।

कड़ी मशक्कत से बच्चों को बाहर निकाला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, बीएमसी और अन्य राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। बचावकर्मियों ने तुरंत बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। अधिकांश छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक छात्र बस के अंदर फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

एक छात्र की मौत

बीएमसी के एम वेस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त के अनुसार, इस हादसे में 10 साल के एक छात्र की मौत हो गई। बस में सवार 18 छात्रों में से 12 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि घायल छात्रों को तत्काल चेंबूर स्थित जेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल चार छात्रों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं।

हादसे की जांच शुरू

हादसे के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और यातायात को कुछ समय के लिए डायवर्ट किया गया। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ कमजोर हो चुका था या हालिया मौसम की वजह से गिरा। इस हादसे ने एक बार फिर बरसात के मौसम में पुराने और जर्जर पेड़ों की निगरानी तथा समय पर उनकी छंटाई की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में गोलीबारी की घटनाओं के पीछे विदेश से संचालित जबरन वसूली करने वाले गिरोह: फडणवीस

बिश्नोई गैंग पर कसेगा शिकंजा!

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में हुई गोलीबारी की घटनाओं के पीछे विदेशों से संचालित संगठित वसूली गिरोहों का हाथ है। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दलों ने इन मामलों तथा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कथित भूमिका की जांच की मांग की है। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है जो विदेशों से आपराधिक गिरोह संचालित कर रहे हैं और धमकियां देने के लिए वीपीएन और वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह राज्य में हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बारे में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक असलम शेख के सवालों का जवाब दे रहे थे। फडणवीस ने कहा कि सरकार पहले से ही कार्रवाई कर रही है और जहां भी जरूरी होगा, अपनी कोशिशें और तेज करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को केंद्र के सामने भी उठाया गया है, क्योंकि आपराधिक नेटवर्क संचालित करने वाले कई लोग विदेश से काम कर रहे हैं।

ये लोग बहुत ताकतवर नहीं हैं

मुख्यमंत्री ने कहा, वे कई लोगों को धमकाते हैं। अगर कोई पैसे देने से मना करता है, तो वे स्थानीय अपराधियों से उस व्यक्ति के घर या दुकान के बाहर गोली चलवाते हैं। उनका मकसद लोगों में डर पैदा करना होता है ताकि वे जबरन वसूली के पैसे दे दें। ये लोग बहुत ताकतवर नहीं हैं; वे विदेश में बैठकर डर फैलाकर जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं की जांच से यह पता चला है कि शूटर को भारत के बाहर से भेजे गए पैसे का इस्तेमाल करके काम पर रखा गया था। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

विस्तृत परामर्श के बाद ही एससी उप-वर्गीकरण पर फैसला लेगी सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और व्यापक परामर्श के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन अनुसूचित जाति समुदायों की पहचान करना है, जिन्हें मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के बावजूद पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा एससी आरक्षण के भीतर कोई नया आरक्षण लागू करने का नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के उप-वर्गीकरण संबंधी निर्देशों के अनुरूप विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने का है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बदर समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई, जहां यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह मामला समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, इसलिए सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएं। सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने तथा सुनवाई करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो अपनी सिफारिशें देगी।

मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। इसका मकसद उन कमियों को दूर करना है जिनका फायदा उठाकर डांस बार चलाने वाले सख्त नियमों से बच निकलते हैं। फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बताया कि प्रस्तावित संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान केवल डांस बार से जुड़े नियमों के तहत ही लाइसेंस ले सकें, जिनमें सख्त शर्तें तय की गई हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा कानून की कमियों का फायदा उठाकर कुछ संचालक डांस बार कानून के बजाय किसी दूसरे कानून के तहत लाइसेंस ले लेते हैं। हम एक संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत ही जारी किए जा सकें। वे कमियां ढूंढ़ते रहते हैं और हम उन्हें दूर करते रहते हैं। मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा ठाणे जिले में चल रहे डांस बार के मुद्दे पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

धर्मांतरण-विरोधी कानून: किसी बेकसूर को नहीं होगी परेशानी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा से पूर्व में पारित धर्मांतरण विरोधी विधेयक एक खास कानूनी ढांचा देगा। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण के मामलों से असरदार ढंग से निपटने के लिए बीएनएस के मौजूदा प्रावधान नाकाफी हैं। विधानसभा में एक सवाल पर फडणवीस ने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। गृह विभाग का कार्यभार संभाल रहे फडणवीस ने कहा, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धर्मांतरण-विरोधी कानून जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए एक खास कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) को और सख्त बनाया है, जिसके तहत धर्मांतरण सहित अवैध गतिविधियों के लिए विदेशी धन का दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। मामले की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच भी प्रतिद्वंद्विता

फडणवीस ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच भी प्रतिद्वंद्विता है और दोनों अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका भी पता लगाएंगे। जबरन वसूली करने वाले इन गिरोहों और संगठित अपराध सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। जिन नागरिकों को जबरन वसूली की धमकियां मिल रही हैं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गिरोहों को हराने के लिए उस डर को खत्म करना जरूरी है जिसे वे पैदा करना चाहते हैं।

साजिश की गहन जांच की मांग

मुद्दा उठाते हुए वडेट्टीवार ने हमलों की साजिश की गहन जांच की मांग की और कहा कि अगर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इसमें कोई भूमिका है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्षी दल के विधायक शेख ने पूछा कि क्या सरकार व्यापारियों से लाखों रुपए की उगाही करने वाले और गोलीबारी की घटनाओं से डर फैलाने वाले संगठित गिरोहों को खत्म करने के लिए कोई खास टीम बनाएगी।

उद्धव ठाकरे को झटका देकर शिंदे गुट से विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया

एमएलसी सचिन अहीर शिंदे गुट में शामिल

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल-पुथल हो रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना (यूबीटी) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सचिन अहीर ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। शिंदे गुट में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सचिन अहीर को लंबे समय तक आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने शिवसेना का रुख किया था। उस समय माना गया था कि उनके पार्टी में आने से आदित्य ठाकरे के लिए मुंबई की वरली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता आसान हुआ। इसके बाद अहीर पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। साल 2022 में शिवसेना के बंटवारे के बाद भी सचिन अहीर उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे थे। हालांकि अब उन्होंने राजनीतिक पाला बदलते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का साथ चुन लिया है। उनके इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए सचिन अहीर का नाम आगे बढ़ाया गया है।

विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन

पाला बदलने के तुरंत बाद सचिन अहीर ने मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में सीधे विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन आवेदन भी दाखिल कर दिया। उद्धव ठाकरे अभी विदर्भ और मराठवाड़ा के बागी सांसदों के क्षेत्रों का दौरा कर मुंबई लौटे ही थे कि उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई में यह बड़ा सियासी खेला हो गया। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखे तंज कसे।

एक-एक करके विकेट गिरते रहेंगे: शिंदे

सचिन अहीर के पार्टी में आने और उपाध्यक्ष पद का पर्चा भरने के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के दौरों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, पिछले हफ्ते हमारी पार्टी में छह सांसदों ने छक्का मारा था, जिससे कुछ लोग बौखलाकर छह-छह निर्वाचन क्षेत्रों की खाक छान रहे हैं। आज मुंबई लौटते ही सचिन अहीर ने भी हमारी तरफ से आकर एक और करारा छक्का जड़ दिया है। विपक्ष का एक-एक करके विकेट गिरता रहेगा।

यह 'ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस' है: आदित्य

उद्धव के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सचिन अहीर के पाला बदलने पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है, यह 'ऑपरेशन टाइगर' नहीं, बल्कि 'ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस' है। शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहीर के महायुति में शामिल होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा, इससे शिव सेना पर कोई असर नहीं होगा। आदित्य ने कहा अहीर ने पार्टी में अहम जिम्मेदारियां संभाली थीं, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण आज पाला बदल लिया।

सांगली का अक्षय बनसोडे 80 हजार की पगार पर कर रहा था सोना तस्करी

55 करोड़ का 37 किलो सोना जब्त

● अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो रहा है मामला

हिंदमाता नेटवर्क @ गुवाहाटी

असम पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सोने की जब्ती की है। गुवाहाटी की डीसीपी शंभवी मिश्रा ने बताया कि इस कार्रवाई में कुल करीब 37 किलोग्राम 24 कैरेट सोना बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 55 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ चांदी के नोड्यूल और फ्लेक्स भी बरामद किए गए हैं। गुवाहाटी पुलिस ने खारघुली में तलाशी अभियान के दौरान 55 करोड़ रुपए कीमत का 37 किलो 24-कैरेट सोना और चार मोबाइल फोन जब्त किए, साथ ही महाराष्ट्र के 32 वर्षीय अक्षय बनसोडे को गिरफ़्तार किया। पुलिस ने बताया कि वह दो महीने से गुवाहाटी में रह रहा था और कथित तौर पर पहले भी 20 किलो सोने की तस्करी कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर रही है।

सांगली का अक्षय बनसोडे गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें सोने की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में 32 वर्षीय आरोपी अक्षय बनसोडे को गिरफ्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। पुलिस को आशंका है कि इसका कोई बड़ा रैकेट हो सकता है। लिहाजा, उसे टैकल करने का प्रयास किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से कनेक्शन का शक

डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, जिसके तार मध्य पूर्वी देशों, म्यांमार और भारत के कई बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से जुड़े हो सकते हैं।

हिंदमाता एंकर: ट्रेन में बिना टिकट सफर करना अब महंगा पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना अब पहले से महंगा, आधार में ईमेल अपडेट कराना अब मुफ्त, एलपीजी, सीएनजी और एटीएफ के दाम भी बदल सकते हैं

1 जुलाई से बदल रहे हैं देश के कई बड़े नियम, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

देशभर में आज से यानी 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं और इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी आधार रेलवे पासपोर्ट क्रेडिट कार्ड और गाड़ियों की कीमतों तक कई नियम नए महीने से बदल रहे हैं। किसी भी परेशानी या एक्स्ट्रा खर्च से बचने के लिए इन बदलावों को पहले से समझ लेना जरूरी है।

आधार में ईमेल अपडेट कराना अब मुफ्त

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या बदलना मुफ्त हो गया है। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे लेकिन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। यह छूट सिर्फ नए आधार मोबाइल ऐप पर मिलेगी। अगर आप किसी और तरीके से ईमेल अपडेट कराते हैं तो पूरा शुल्क देना होगा। इसके साथ ही पुराना एमआधार ऐप बंद किया जा रहा है और उसकी जगह नया आधार ऐप लाया गया है जिसमें ज्यादा सुरक्षा और आसान इस्तेमाल वाले फीचर दिए गए हैं।

पासपोर्ट बनवाना अब पहले से महंगा

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। यह बदलाव 20 जून को जारी पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत हुआ है और 1 जुलाई से लागू हो रहा है। अब 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है और इसी का तत्काल शुल्क 3500 से बढ़कर 5000 रुपए हो गया है। वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2000 से बढ़कर 3500 रुपए और तत्काल शुल्क 4000 से बढ़कर 6000 रुपए कर दिया गया है। पासपोर्ट दोबारा बनवाने खोए या खराब पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के साथ नाबालिगों के पासपोर्ट पर भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे। हालांकि पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बड़ों का पासपोर्ट पहले की तरह दस साल तक मान्य रहेगा।

ट्रेन में बिना टिकट सफर करना अब महंगा पड़ेगा

1 जुलाई से बिना टिकट या बिना सही टिकट यात्रा करने पर कम से कम जुर्माना 250 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा। यह बदलाव जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 में किया गया है। रेलवे का कहना है कि यह कदम बिना टिकट यात्रा रोकने और टिकट जांच को सख्त करने के लिए उठाया गया है। कोर्ट की ओर से दी जाने वाली ज्यादा से ज्यादा सजा पहले जैसी ही रहेगी जिसमें छह महीने तक की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

गाड़ियां खरीदना भी महंगा होगा

नई कार खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए जुलाई की शुरूआत भारी पड़ सकती है। टाटा मोटर्स अपनी पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम 1 जुलाई से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा रही है। कंपनी अपने कमर्शियल वाहनों के दाम भी 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा रही है।

पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी रोक हटेगी

वेस्ट एशिया संकट के चलते सरकार ने 12 जून को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ अस्थायी पाबंदियां लगाई थीं। इसके तहत रिटेल पंप पर हर ग्राहक या वाहन को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। अब ये पाबंदियां 1 जुलाई से हटा दी हैं।

नकली पिस्तौल से ज्वेलर्स शोरूम लूट की कोशिश

48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

हिंदमाता संवाददाता @ वसई

नालासोपारा पूर्व स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में प्लास्टिक की नकली पिस्तौल दिखाकर दिनदहाड़े लूट का प्रयास करने वाले एक शातिर अपराधी को तुलिंज अपराध शाखा ने घटना के महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कन्नन मुर्गेश तेवर (50) के रूप में हुई है, जिसे मुंबई के वडाला इलाके से पकड़ा गया। पुलिस इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है।

सीसीटीवी बंद होने से बढ़ी चुनौती

पुलिस के अनुसार, 25 जून 2026 को दोपहर करीब 12.30 बजे दो अज्ञात बदमाश नालासोपारा पूर्व के नागिनदासपाड़ा स्थित साई ज्योत अपार्टमेंट में मौजूद नीलम ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए। आरोपियों ने दुकान मालिक भोलाराम खीमाराम चौधरी (52) को प्लास्टिक की नकली पिस्तौल दिखाकर सोने के आभूषण लूटने का प्रयास किया। शिकायत के आधार पर तुलिंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिससे पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई।

आरोपी पर मकोका सहित कई मामले

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तुलिंज अपराध शाखा ने तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के वडाला पूर्व स्थित कोकरी डिपो क्षेत्र में जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि कन्नन तेवर एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उसके खिलाफ मुंबई के सायन, दादर तथा एंटॉप हिल पुलिस थानों में लूट और डकैती के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उस पर मकोका के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दी।

नवी मुंबई मनपा के बेड़े में शामिल होंगी 150 नई सीएनजी बसें

• ई-बसों की खराबी के चलते ने बदला फैसला

हिंदमाता संवाददाता @ नवी मुंबई

नवी मुंबई मनपा परिवहन उपक्रम में सीएनजी से चलने वाली 150 नई बसें एक साल के अंदर मनपा के बेडे में शामिल की जाएंगी। इनमें से 30 बसें पहले फेज में शामिल की जा चुकी हैं। विश्वास व्यक्त किया गया है कि इससे यात्रियों को बेहतर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकेगी। इलेट्रिक बसों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नवी मुंबई महानगर परिवहन उपक्रम ने सीएनजी बसों को खरीदने का निर्णय लिया है।

बढ़ाए जाएंगे बसों के मार्ग

नवी मुंबई मनपा के ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी एनएमएमटी के बेड़े में अभी 350 बसें हैं। ये बसें नवी मुंबई से पनवेल, उरण, खोपोली, कल्याण डोंबिवली, बोरीवली मंत्रालय तक चल रही हैं। एनएमएमटी बसों में महिलाओं से आधी टिकट ली जा रही है।

बुजुर्गों को दिया जा रहा डिस्काउंट

वरिष्ठ नागरिकों को किराए में डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस वजह से एनएमएमटी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी ज्यादा है। इसलिए, यात्रियों की मांग है कि कई रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि, बसों की कमी के कारण कई रूटों पर बसें नहीं बढ़ाई जा सकतीं। इसलिए, यात्रियों को बस का इंतजार करना पड़ता है। बसों की संख्या बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसके लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पिछले साल 150 नई बसें खरीदने का फैसला किया था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सीएनजी से चलने वाली बसें खरीदने का फैसला किया था। नवी मुंबई मनपा परिवहन उपक्रम के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जिन बसों का आर्डर दिया गया था वह बसें आनी शुरू हो गई हैं।

आए दिन खराब हो रही हैं ई बसें

नवी मुंबई इलेक्ट्रकल बसें अक्सर सड़क पर खराब हो जाती हैं, इस कारण यात्रियों को परेशानी होती है। यात्रियों और ड्राइवरों के बीच बहस होती है। इसलिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेट्रिक बसें खरीदने के बजाय सीएनजी बसें खरीदने का फैसला किया है।

अगले महीने 20 बसें आएंगी

अभी, पहले फेज में ये 30 बसें ट्रांसपोर्ट सेवा में आ गई हैं। बाकी की बसें धीरे धीरे आती रहेंगी। अब तक जो बसें आ गई हैं, वे घनसोली ट्रांसपोर्ट डिपो में खड़ी हैं। बीस बसें अगले महीने आएंगी। यह जानकारी ट्रांसपोर्ट सूत्रों से मिली है। ये सभी बसें ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खुद खरीदी हैं। इसलिए इन बसों से होने वाली सारी इनकम ट्रांसपोर्ट के अकाउंट में जमा होगी। इसलिए, कंपनी ने भरोसा जताया है कि यह बस ट्रांसपोर्ट के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा, पैसेंजर भी इस बस से अच्छी बस सर्विस का मजा ले पाएंगे।

शॉर्ट स्टोरी

स्मार्ट मीटर के विरोध में आयटक का प्रदर्शन

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

टोरंट पावर द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की अनिवार्यता के विरोध में मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार (आयटक) संगठन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के नेतृत्व में प्रांत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों श्रमिकों ने कल्याण नाका से रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रांत अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली बिल का बोझ बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की कि इसे अनिवार्य न बनाया जाए। ज्ञापन में निर्माण श्रमिकों के लिए 10 हजार रुपए मासिक पेंशन, न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए प्रतिमाह, नकद आर्थिक सहायता, नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई तथा सीआरपी जवानों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने टोरंट पावर का अनुबंध जनवरी 2027 के बाद बिना समीक्षा आगे न बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन धरना

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

दिव्यांगों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अपंग विकास महासंघ के बैनर तले मंगलवार से भिवंडी महानगरपालिका मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन लंबे समय से दिव्यांगों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जिसके विरोध में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलनकारियों ने दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने, एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मनपा की ओर से लाइसेंस प्राप्त स्टॉलों का आवंटन तथा स्टॉल लाइसेंस की शर्तों में राहत देने की मांग की। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए विवाह सहायता अनुदान, खिलाड़ियों को सम्मान राशि, नि:शुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण, परामर्श एवं काउंसलिंग केंद्र की स्थापना तथा वर्ष 2017-18 से लंबित दिव्यांग कल्याण निधि का तत्काल वितरण करने की भी मांग उठाई गई। महासंघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस निर्णय होने तक महानगरपालिका मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

'सफाई मित्र' ऐप पर उठे सवाल

हिंदमाता संवाददाता @ वसई

वसई-विरार महानगरपालिका की ओर से शहर को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'सफाई मित्र' ऐप अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका है। जनजागरूकता के अभाव के कारण साढ़े तीन महीनों में इस ऐप पर केवल 714 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ऐप की प्रभावशीलता और उसके प्रचार-प्रसार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महानगरपालिका का दावा है कि ऐप के माध्यम से दर्ज सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण किया गया है। हालांकि, शहर के कई इलाकों में अब भी कचरे के ढेर और गंदगी देखी जा रही है। ऐप के जरिए नागरिक गंदगी की तस्वीर अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का दावा किया गया था। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता सुरेंद्र सिंह राज ने कहा कि केवल ऐप शुरू करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान, प्रचार-प्रसार और नियमित निगरानी जरूरी है। वहीं, स्थानीय नागरिकों ने भी ऐप का व्यापक प्रचार, हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने और लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की मांग की है, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके।

प्रदीप शर्मा ने सादगी से मनाई शादी की सालगिरह

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

जाने माने एनकाउंटर स्पेसलिस्ट व सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्था पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने सादगी पूर्वक शादी की सालगिरह मनाई। जब कि उनकी संस्था के कार्यकताओं ने आग्रह किया था कि जोर शोर से मनाया जायेगा। परंतु स्वावलंबन महिला समिति की अध्यक्षा स्वीकृति प्रदीप शर्मा ने भी सादगी से ही मनाने का फैसला किया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि देश और राज्य इस समय संकट की अवस्था से गुजर रहे हैं। और जनता भी रोज नये आयाम तलाशने में परेशान है। इसलिये सालगिरह ओपचारिकता मात्र ही उचित रहेगा। शर्मा दाम्पत्य ने एक दूसरे को गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं प्रदान की। और बड़ी संख्या में लोग इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं देने के लिए दूरदराज से अँधेरी आये। प्रदीप शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि आज आप सब का जो अपनापन और प्यार मिला है इससे बड़ी दौलत हमारे जीवन में कुछ भी नही है। और इसे मैं धरोहर के रूप में संजो कर रखूंगा। और हमारा फाउंडेशन दोहरी ताकत व ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता रहेगा। अंत में शर्मा ने सभी शुभचिंतकों का दिल से आभार जताया।

भ्रष्ट अधिकारियों पर मनपा की कार्रवाई शुरू

एसीबी मामलों में अहम पदों से हटाने की प्रक्रिया शुरू

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर

उल्हासनगर महानगरपालिका ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मनपा आयुक्त मनीषा अव्हाले के निर्देश पर शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद 'कायद्याने वागा लोकचलवाली' के अध्यक्ष राज असरोंडकर ने 30 जून से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है।

सरकारी आदेश का पालन

सरकारी निर्देशों के अनुसार एसीबी के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गए कर्मचारियों को नीतिगत निर्णय या जनसंपर्क से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। संगठन का दावा है कि मनपा में ऐसे 23 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर 16 और 23 जून को मनपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया गया था।

दो अधिकारियों से पद वापस

उपायुक्त डॉ. दीपाली चौगले के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद प्रशासन ने अनधिकृत निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी गणेश शिम्पी और सुरक्षा अधिकारी यशवंत संगके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वापस ले लीं। यशवंत संगके का तबादला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका में कर दिया गया है। प्रशासन ने शेष अधिकारियों के मामलों की भी समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से सरकारी आदेश लागू करने का आश्वासन दिया है।

आंदोलन रहेगा जारी

इस आंदोलन को कांग्रेस, विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों का समर्थन मिला। राज असरोंडकर और मीडिया प्रभारी प्रफुल केदारे ने कहा कि कार्रवाई शुरू होने से आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

इंस्टाग्राम पेज संचालक गिरफ्तार

आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर कथित उगाही का आरोप, खंडनी पथक की कार्रवाई

हिंदमाता संवाददाता @ मुंब्रा

ठाणे पुलिस के खंडनी पथक ने मुंब्रा से "सिर्फ मुंब्रा" नामक इंस्टाग्राम पेज संचालित करने वाले हसन नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर उनकी छवि धूमिल करने तथा वीडियो हटाने के बदले कथित रूप से पैसे मांगने का आरोप है। कार्रवाई समाजसेवी बिलाल शेख उर्फ जसबीर की शिकायत पर की गई।

शिकायत के बाद जाल बिछाया

शिकायतकर्ता बिलाल शेख के अनुसार, उनके बारे में भी आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया था। वीडियो हटाने की मांग करने पर आरोपी ने कथित तौर पर रुपए मांगे। इसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और सबूत के तौर पर आरोपी के खाते में कुछ राशि भेजी। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

तकनीकी जांच से गिरफ्तारी

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मोबाइल इंटरनेट का कम इस्तेमाल करता था और अलग-अलग स्थानों के वाई-फाई नेटवर्क से वीडियो अपलोड करता था। तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र के एक वाई-फाई कनेक्शन का सुराग मिला। बाद में मोबाइल सक्रिय होते ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर मुंब्रा से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

पूरे नेटवर्क की जांच

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े थे। फिलहाल मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस कथित पूरे नेटवर्क तथा उसके पीछे मौजूद अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

टीईटी पेपर लीक में मास्टरमाइंड की पत्नी गिरफ्तार

अदालत ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

महाराष्ट्र के बहुचर्चित टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर मंगलवार को कोनगांव पुलिस ने भिवंडी अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

आर्थिक लेन-देन की जांच

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी की तलाश में विशेष टीम बिहार पहुंची थी, लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुमन कुमारी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पेपर लीक से जुड़े आर्थिक लेन-देन की कड़ियां उसके बैंक खातों से जुड़ी हो सकती हैं।

जांच का दायरा बढ़ा

अब तक की जांच में सामने आया है कि टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया और दिल्ली के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचाकर लीक किया गया। इस मामले में पहले तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुमन कुमारी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या चार हो गई है, जबकि आगरा से जुड़े चार अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।

पूरे नेटवर्क पर नजर

कोनगांव पुलिस बैंक लेन-देन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि सुमन कुमारी ने जांच में सहयोग किया है और उनके खिलाफ आर्थिक लेन-देन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस को पूछताछ से मामले में और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

तिरपाल डालते समय गिरने से व्यक्ति की मौत

हिंदमाता संवाददाता @ नालासोपारा

लगातार बारिश के बीच घर की टपकती छत पर तिरपाल डालना एक 50 वर्षीय व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ। नालासोपारा पूर्व के तुलिंज थाना क्षेत्र में टिन की छत टूटने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए ओमप्रकाश रामजीयावन पांडे की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ओमप्रकाश पांडे बारिश का पानी रोकने के लिए अपने घर की टिन की छत पर तिरपाल बिछा रहे थे। इसी दौरान टिन की चादर अचानक टूट गई और वह नीचे गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें तत्काल आइकॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 जून की शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने किसी पर भी संदेह या शिकायत से इनकार किया है। तुलिंज पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेड़ गिरने से कार चकनाचूर

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

सोमवार देर रात हुई हल्की बारिश के बाद वहाळ तालाब क्षेत्र में एक विशाल पेड़ अचानक जड़ सहित उखड़कर सड़क किनारे खड़ी कार पर गिर गया। हादसे में वैगनआर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार में कोई सवार नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, मानसरोवर रोड स्थित वहाळ तालाब इलाके में पुराना पेड़ कार (एमएच-01-ईडब्ल्यू-2032) पर गिर पड़ा, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि चालक कुछ ही देर पहले कार खड़ी कर घर गया था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ की शाखाएं हटाकर सड़क पर यातायात बहाल कराया। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पुराने और जर्जर पेड़ों का सर्वे कर समय रहते उनकी छंटाई या हटाने की मांग की है, ताकि बारिश के मौसम में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

40 साल पुराने अखबार विक्रेता को हटाने का नोटिस

हिंदमाता संवाददाता @ भायंदर

मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर पिछले करीब 40 वर्षों से अखबार बेच रहे एक विक्रेता को महानगरपालिका द्वारा दुकान हटाने का नोटिस दिए जाने से मीरा-भायंदर समाचार पत्र विक्रेता संघ में नाराजगी है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से इस मामले में राहत देने की मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।

सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई

महानगरपालिका के अनुसार, मीरा रोड स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में फेरीवालों के कारण यात्रियों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद स्टेशन परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर उसका सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसी अभियान के तहत फेरीवालों और स्टॉल संचालकों को स्थान खाली करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें पुराने अखबार विक्रेता भी शामिल हैं।

238 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट

हिंदमाता संवाददाता @ मीरा-भायंदर

विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष-1 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 मामलों में जब्त करीब 238.18 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल को नष्ट कर दिया।

जब्त सामग्री का निस्तारण

पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के मार्गदर्शन और मादक पदार्थ मुद्देमाल नाश समिति की अनुमति के बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जब्त 326 किलो 559 ग्राम मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। इनमें गांजा, चरस, मेफेड्रोन (एमडी), हेरोइन, इफेड्रिन, कोकीन, कफ सिरप तथा ट्रामाडोल टैबलेट्स शामिल थीं। इसके अलावा दो मामलों में जब्त 1,541 किलो 356 ग्राम कच्चा माल भी नष्ट किया गया।

अधिकारियों की मौजूदगी

यह कार्रवाई 29 जून को तळोजा (पनवेल) स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के संयंत्र में की गई। अभियान का संचालन पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय शिंत्रे के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (अपराध) संदीप डोईफोडे, पुलिस निरीक्षक समीर शेख सहित अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिंदमाता एंकर: 58 प्रतिशत हुई मैपिंग, 30 जून से घर-घर जाएंगे बीएलओ

ठाणे जिले में मतदाता सूचियों का एसआईआर प्रोग्राम

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

चुनाव आयोग के निदेर्शों के अनुसार ठाणे जिले में मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी लागू कर दिया गया है। ठाणे जिले में वोटर लिस्ट को अचूक और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला चुनाव अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के नेतृत्व में एसआईआर प्रोग्राम के तहत नियुक्त किए गए बीएलओ यानी बूथ लेबल ऑफिसर 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक घर घर जाएंगे। जिलाधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के घोष वाक्य के अनुसार किसी भी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा लेकिन किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। स्पेशल रिवीजन में मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करनी होगी। इसलिए बीएलओ के माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म भर कर देना होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की मदद भी ली जाएगी। 2002 की वोटर लिस्ट ग्राहय, वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में मतदाता या उसके माता पिता का नाम है और उन्होंने वोट दिया है तो वे भी पात्र माने गए हैं।

जिले में 74.50 लाख से ज्यादा मतदाता

एक पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि एसआईआर के तहत ठाणे जिले की 18 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6 हजार 894 पोलिंग स्टेशनों से जुड़े इस समय तक कुल 74 लाख 50 हजार 515 मतदाता हैं। इनमें से 58.15 प्रतिशत मतदाताओं की मेपिंग (मिलान) हुआ है। जिले में सर्वाधिक शहरी भाग होने के चलते मिलान में समस्या आई है,जबकि भिवंडी ग्रामीण एवं शाहपुर जैसे आदिवासी व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 71 से 81 प्रतिशत तक मतदाता सूचियों की मेपिंग हो गई है। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति उनकी एरिया के हिसाब से कर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। चल रही ऑनलाइन मैपिंग, 'एसआईआर मैपिंग' के परसेंटेज का भी रिव्यू किया गया है।

5 अगस्त को पब्लिस होगी अंतिम मतदाता सूची

इस विशेष कैंपेन को लेकर जिलाधिकारी ने साफ किया कि 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ हर घर जाकर गणना फॉर्म भरेंगे। इसमें नाम, जेंडर, उम्र, रिश्ता, परिवार की संख्या, माता-पिता की डिटेल्स जैसी जानकारी शामिल होगी। जो वोटर्स उपलब्ध नहीं हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, मर चुके हैं या जिनकी डबल एंट्री हैं, उनकी सेंटर-वाइज लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पंचायत समिति, मनपा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। इसके बाद, 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिन वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है या जिनकी जानकारी में अंतर है, उन्हें भी दावे या आपत्तियों के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक के समय दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, सुधार और माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 6 की लिस्ट में फॉर्म 9, फॉर्म 7 के लिए फॉर्म 10, सुधार के लिए फॉर्म 8, माइग्रेशन के लिए फॉर्म 11 (चुनाव क्षेत्र 11ए के अंदर माइग्रेशन और चुनाव क्षेत्र 11बी के बाहर माइग्रेशन) वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश किया जाएगा। पूरी लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश की जाएगी।

जरूरी होंगे ये सबूत

जिलाधिकारी ने डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि इस खास कैंपेन में नागरिकता के सबूत के बारे में जरूरी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके मुताबिक, अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो जन्म की तारीख या जन्म की जगह साबित करने वाला कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो माता या पिता में से किसी एक का भारत में जन्म का प्रूफ अटैच करना होगा। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोगों के माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो एप्लीकेंट के जन्म के समय उनके वैलिड पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जमा करनी होगी। भारत के बाहर जन्मे लोगों के लिए, विदेश में इंडियन एम्बेसी द्वारा जारी किया गया बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रूफ और जिन्होंने नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता हासिल की है, उनके लिए डिक्लेरेशन के साथ सिटिजनशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफि केट जमा करना जरूरी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधारकार्ड या राशनकार्ड वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा।

राजनीतिक दलों से भी अपील

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने नागरिकों के साथ राजनीतिक दलों से भी बीएलए नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रूपाली भालके, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वैशाली माने, एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर प्रशांत रोडे, विठ्ठल डाके, योगेश गोडसे, सुनील पवार, धीरज चव्हाण, तहसीलदार प्रदीप कुडाल के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी और अलग-अलग मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राजनीतिक दलों को बताया गया कि 2026 की लिस्ट में वोटर की छपी हुई डिटेल्स, सेंसस फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों से यह भी अपील की गई है कि वे उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें जहां लिस्ट का हिस्सा 40 परसेंट से कम है। कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया है कि फाइनल वोटर लिस्ट छपने तक एडमिनिस्ट्रेशन हर हफ़्ते रिव्यू मीटिंग करेगा।

कैडबरी जंक्शन पर सीमेंट टैंकर पलटा, घंटों लगा जाम

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

मुंबई-नाशिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैडबरी जंक्शन के पास मंगलवार दोपहर सीमेंट पाउडर से भरा एक टैंकर पलट जाने से लंबा यातायात जाम लग गया। हादसे के कारण घोड़बंदर, भिवंडी, माजीवाड़ा और वसंत विहार की ओर जाने वाले हजारों वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

महत्वपूर्ण मार्ग पर बाधा

नवी मुंबई के जेएनपीए बंदरगाह, भिवंडी, नाशिक और समृद्धि महामार्ग से ठाणे, घोड़बंदर तथा गुजरात की ओर जाने वाले हजारों भारी वाहन इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। माजीवाड़ा चौक पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण उन्हें फ्लाईओवर से होकर कैडबरी जंक्शन के तीखे मोड़ से गुजरना पड़ता है। इसी मोड़ पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे यातायात बार-बार प्रभावित होता है।

इस्लाम अपनाने के बाद नहीं मिलेगा एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट का फायदा

• बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला, जानें बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने माना कि धर्म परिवर्तन के बाद इस विशेष कानून के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं।

बाम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर खंडपीठ की न्यायमूर्ति वृषाली वी जोशी की सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक दंपति को 'एट्रोसिटी एक्ट' के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया, जिन पर उनके ही एक रिश्तेदार ने केस किया था। कोर्ट ने माना कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है तो 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' (अत्याचार कानून) के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा हैं। पीड़ित महिला का अपने पति के रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। साल 2015 में जब महिला की ननद और ननदोई उनके घर रहने आए, तब घर में स्वच्छता बनाए रखने, कम पानी का इस्तेमाल करने और शौचालय साफ रखने जैसी मामूली बातों पर उनके बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पूर्व जाति की जानकारी होने के बावजूद उसे सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्द कहे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वृषाली वी. जोशी की बेंच ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने खुद स्वीकार किया कि उसके पति मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इसलिए शादी के वक्त उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था। तब से वह लगातार मुस्लिम रीति-रिवाजों का पालन कर रही है और धर्म परिवर्तन के बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया था। आरोपियों की तरफ से पेश वकील सत्यव्रत जोशी ने अदालत में दलील दी कि यह पूरी तरह से एक ही परिवार का सिविल (संपत्ति) विवाद है। कोर्ट का यथास्थिति का आदेश उनके पक्ष में होने के कारण महिला ने द्वेषवश यह झूठी एफआईआर दर्ज कराई है।

सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी हुआ जिक्र

वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक एसवी गवंड ने भी सुप्रीम कोर्ट के 'चिंथाडा आनंद' मामले का हवाला देते हुए सहमति जताई कि धर्म परिवर्तन के बाद महिला एट्रोसिटी एक्ट का लाभ लेने की हकदार नहीं है। भले ही वह धर्म परिवर्तन से पहले अनुसूचित जाति से संबंधित थी। हालांकि, इस पहलू का भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों से जुड़े आरोपों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दंपति को एट्रोसिटी एक्ट के आरोपों से तो पूरी तरह मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया, लेकिन साफ किया कि प्राथमिकी में दर्ज अन्य अपराधों के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को अदालत में मुकदमे का सामना करना ही होगा।

खराब सड़कों पर हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार

बदहाल सड़कें और खुले मैनहोल पर जताई नाराजगी

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई की जर्जर सड़कों और खुले मैनहोल के मुद्दे पर मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि पिछले दो दशकों से यह समस्या बनी हुई है और अब समय आ गया है कि बीएमसी स्थायी समाधान निकाले। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हर साल बहाने नहीं चलेंगे

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दहिसर से फोर्ट तक सफर करने वाले लोगों को सैकड़ों झटके सहने पड़ते हैं। वर्ष 2007 में भी सड़क सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 2026 तक हालात नहीं बदले। अदालत ने बीएमसी से सवाल किया कि हर वर्ष वही समस्याएं सामने आती हैं और हर बार नए बहाने पेश किए जाते हैं। न्यायालय ने दुनिया के प्रमुख शहरों की तरह वैज्ञानिक तरीके से सड़क निर्माण करने की सलाह भी दी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गडकरी ने टिप्पणी की कि ठाणे की सड़कों की स्थिति तो मुंबई से भी अधिक खराब हो चुकी है।

मैनहोल सुरक्षा पर भी सख्ती

उच्च न्यायालय ने खुले मैनहोल और उनके नीचे सुरक्षा जालियां लगाने के आदेश के अधूरे पालन पर भी नाराजगी जताई। अदालत को बताया गया कि अभी भी तीन हजार से अधिक मैनहोल पर ढक्कन और सुरक्षा जालियां लगाई जानी बाकी हैं। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि उसे आंकड़े नहीं, बल्कि यह भरोसा चाहिए कि इस वर्ष मैनहोल से जुड़ी किसी भी दुर्घटना में एक भी नागरिक की जान नहीं जाएगी। अदालत ने बीएमसी को नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

शिवसेना यूबीटी से बगावत के बावजूद दल-बदल की कार्रवाई से बच जाएंगे सचिन अहीर!

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर दलबदल विरोधी कानून को लेकर चचाएं तेज हो गई हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने और उपसभापति पद के लिए नामांकन भरने के बाद कानूनी गलियारों में एक बड़ा सवाल तैर रहा है। सवाल यह है कि क्या अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने पर सचिन अहीर की विधायकी चली जाएगी? जानकारों और विधायिका के नियमों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेहद सोची-समझी कानूनी रणनीति के तहत सचिन अहीर को अपने पाले में किया है। सचिन अहीर के इस कदम के बावजूद उन पर दलबदल विरोधी अधिनियम के तहत कोई दंडात्मक या अयोग्यता की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके पीछे संविधान की दसवीं अनुसूची का एक बेहद महत्वपूर्ण और खास प्रावधान ढाल बनकर खड़ा है, जिसने ठाकरे गुट के कानूनी रणनीतिकारों को भी असमंजस में डाल दिया है।

क्या है संविधान की दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 5

दरअसल, भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जो दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है, उसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल हैं। इनमें से अनुच्छेद 5 कुछ विशेष संवैधानिक पदों पर आसीन या निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को इस कठोर कानून से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करता है। इस नियम के तहत यदि कोई सदस्य सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष/उपसभापति चुना जाता है, तो उसे अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से अलग होने की कानूनी आजादी मिलती है।

उपसभापति पद बनते ही मिलेगी कानूनी सुरक्षा

इस नियम के मुताबिक, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, तथा राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष व उपसभापति के पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को दल-बदल कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। चूंकि सचिन अहीर ने महायुति की तरफ से विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है और सदन में महायुति का स्पष्ट बहुमत है, ऐसे में उनका चुना जाना लगभग तय है। पद संभालते ही उन्हें यह विशेष संवैधानिक सुरक्षा कवच मिल जाएगा।

'ऑपरेशन टाइगर' के बीच उद्धव को मुंबई में पटखनी

■ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे जब एक तरफ राज्य भर में घूमकर महायुति और एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं, ठीक उसी समय शिंदे ने उनके गढ़ मुंबई में यह बड़ा 'सर्जिलकल स्ट्राइक' किया है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे की जीत की मुख्य रीढ़ रहे सचिन अहीर को अपने साथ लाकर शिंदे ने न केवल ठाकरे समूह के विधायकों की संख्या घटाकर 5 कर दी है, बल्कि आगामी चुनावों से पहले मुंबई में अपनी राजनीतिक जमीन को भी कानूनी और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत कर लिया है।

एक रात के 2 लाख एक्ट्रेस के जिस्म का सौदा

मुंबई के गिरगांव में हाई-प्रोफाइल देह व्यापार का पदार्फाश

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मायानगरी मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपे एक बेहद काले और घिनौने सच का पदार्फाश हुआ है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरगांव इलाके के एक नामी और प्रतिष्ठित होटल में छापेमारी कर एक बेहद हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी दो अभिनेत्रियों को इस दलदल से सुरक्षित बाहर निकाला है। इस घिनौने व्यापार को संचालित करने और अभिनेत्रियों के जिस्म का सौदा करने के आरोप में पुलिस ने फिल्म जगत की ही एक नामी महिला मेकअप आर्टिस्ट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभिनेत्रियों की इस रैकेट में संलिप्तता की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा जगत में सनसनी मच गई है।

पुलिस ने महिला मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया

मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 को एक बेहद पुख्ता और गुप्त सूचना मिली थी कि गिरगांव के एक जाने-माने बड़े होटल में फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का एक हाई-प्रोफाइल देह व्यापार का नेटवर्क सक्रिय है। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस की टीम ने फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में जाल बिछाया और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद को सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बताती है और अभिनेत्रियों को सीधे ग्राहकों तक सप्लाई करने का काम करती थी।

एक रात के लिए 2 लाख रुपए में हुआ था सौदा

पुलिस जांच और पूछताछ में इस रैकेट के वित्तीय लेन-देन को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी महिला मेकअप आर्टिस्ट ने दोनों अभिनेत्रियों के लिए एक रईस ग्राहक से कुल 2 लाख रुपए का सौदा तय किया था। इस डील के तहत प्रति अभिनेत्री एक रात के लिए 1 लाख रुपए की दर तय की गई थी। ग्राहकों से मोटी रकम वसूलने और अपना बड़ा कमिशन काटने के बाद यह महिला दोनों अभिनेत्रियों को कार से गिरगांव के उसी होटल में लेकर पहुंची थी, जहां पहले से मुस्तैद क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा।

मराठी और बॉलीवुड की बंगाली अभिनेत्री को दिया गया था पैसों का लालच

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस दलदल से बचाई गई युवतियों में से एक लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हैं और दूसरी बंगाली मूल की अभिनेत्री हैं, जिसने कई बॉलीवुड फिल्मों और छोटे पर्दे (टीवी सीरियल्स) में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाई हैं। जांच में सामने आया है कि रेस्क्यू की गई मराठी अभिनेत्री मूल रूप से महाराष्ट्र के एक ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है और वह फिल्मों में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए मुंबई आई थी। हालांकि, काम न मिलने और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर आरोपी मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें पैसों का भारी लालच दिया और धीरे-धीरे वेश्यावृत्ति के इस काले धंधे में धकेल दिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस रैकेट के तार फिल्म इंडस्ट्री के और किन-किन बड़े चेहरों और दलालों से जुड़े हुए हैं।

पहले आओ-पहले पाओ, रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर

मुंबई से सूरत तक एटीवीएम फैसिलिटेटर पदों के लिए होगी आवेदन

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा और टिकट काउंटर पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल करते हुए नौकरी का सुनहरा मौका दिया है। रेलवे प्रशासन ने मुंबई से सूरत के बीच स्थित विभिन्न स्टेशनों के लिए 175 ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति का निर्णय लिया। यह नियुक्तियां दो वर्ष के ठेका आधार पर की जाएंगी। साथ ही चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा और चयनित उम्मीदवारों को टिकट बिक्री पर कमीशन भी मिलेगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक सबसे अधिक 14-14 रिक्तियां बांद्रा और अंधेरी स्टेशनों पर हैं, जबकि सांताक्रूज में 12, जोगेश्वरी में 9, मुंबई सेंट्रल, गोरेगांव, मलाड और बोरीवली में 8-8, माहिम, ग्रांट रोड और विले पार्ले सहित अन्य स्टेशनों पर भी रिक्तियां उपलब्ध हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में आम नागरिकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और संबंधित रेलवे स्टेशन वाले जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। चयन से पहले पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा। यह अवसर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों, उनके पति-पत्नी, वयस्क बच्चों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है।

जमा करने होंगे सुरक्षा राशि

सुरक्षा जमा राशि के रूप में मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, सूरत और वापी स्टेशनों के लिए 50 हजार रुपए और अन्य सभी स्टेशनों के लिए 25 हजार रुपए जमा कराने होंगे। हालांकि, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा जमा राशि से छूट दी गई है।

टिकट जारी करेंगे एटीवीएम फैसिलिटेटर

चयनित एटीवीएम फैसिलिटेटर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी करेंगे और यात्रियों को मशीन के उपयोग में सहायता प्रदान करेंगे। उन्हें सबअर्बन टिकटों की बिक्री पर 3 प्रतिशत और गैर-उपनगरीय मेल व एक्सप्रेस टिकटों पर 1 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा।

स्कूल में खूनी वारदात

टीसी लेने आया था नाबालिग छात्र

हो गई बहस, क्लास टीचर पर चाकू से हमला

हिंदमाता नेटवर्क @ छत्रपति संभाजीनगर

छत्रपति संभाजीनगर के छावनी क्षेत्र से शिक्षा जगत को शर्मसार और हैरान कर देने वाली एक बेहद हिंसक घटना सामने आई है। यहां के एक प्रतिष्ठित स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आए एक नाबालिग छात्र ने अपने ही क्लास टीचर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में स्कूल स्टाफ द्वारा तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमलावर छात्र को हथियार सहित हिरासत में ले लिया है।

बैग से चाकू निकाल कर किया हमला

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी नाबालिग छात्र स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) निकलवाने के लिए आया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी इस छात्र का अपने क्लास टीचर के साथ कुछ मुद्दों को लेकर पुराना विवाद चल रहा था और वह उनसे काफी नाराज था। आज जब वह टीसी लेने काउंटर पर पहुंचा, तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते इस पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गुस्से में आकर छात्र ने अपने बैग से पहले से छिपाकर रखा हुआ धारदार चाकू निकाला और शिक्षक के पेट और हाथों पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाया था हथियार

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की शुरूआती पूछताछ में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिरासत में लिए गए नाबालिग छात्र ने कबूल किया है कि उसने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू कुछ दिनों पहले ही एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके मंगाया था। पुलिस अब इस बिंदु की भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या छात्र इस हमले की योजना काफी समय से बना रहा था और क्या उसके माता-पिता या स्कूल प्रशासन को छात्र के पास घातक हथियार होने की जरा भी भनक थी। पुलिस ने छात्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सुरक्षा को लेकर बुलाई गई आपात बैठक

इस खूनी संघर्ष के बाद स्कूल के अन्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में भारी डर और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्कूल परिसर के भीतर और बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ, स्कूल प्रबंधन ने इस सुरक्षा चूक को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें स्कूल के मुख्य गेट पर छात्रों के बैग की चेकिंग और सुरक्षा गार्डों की मुस्तैदी को और अधिक कड़ा करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, घायल शिक्षक के शरीर पर गहरे जख्म आए हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वे खतरे से बाहर हैं।

जैन समुदाय के विकास के लिए 100 करोड़ का फंड

शिक्षा और स्वरोजगार को मिलेगा बड़ा सहारा

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्रीयन जैन समुदाय की शैक्षणिक प्रगति और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त महामंडल के बीच एक महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत महाराष्ट्र में जैन समुदाय के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी ने इस फैसले को समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। यह समझौता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त महामंडल के मुख्यालय में संपन्न हुआ।

प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में हुए हस्ताक्षर

इस अवसर पर जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी और प्रबंध निदेशक मेधना शिंदे ने हस्ताक्षर किए, वहीं राष्ट्रीय महामंडल की ओर से महाव्यवस्थापक अनिल कुमार ने संस्थान की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आभा रानी सिंह की मुख्य उपस्थिति में इस करार पत्र पर हस्ताक्षर किए, इस दौरान संदीप भंडारी, विकास आच्छा और विपिन जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

उच्च शिक्षा का अवसर

इस नई नीति और समझौते के बाद जैन समुदाय के कम आय वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आगे की राह आसान होगी, उन्हें देश या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहद सरल शर्तों पर और कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी।

सर्पदंश से 6 वर्षीय मासूम की मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ चंद्रपुर

चंद्रपुर जिले के लछमागुडा गांव में सर्पदंश का शिकार हुए छह वर्षीय बालक की समय पर उपचार नहीं मिलने से दुखद मृत्यु हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण आगे के उपचार के लिए ले जाने में देरी होने का गंभीर आरोप परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। इस घटना के बाद एक बार फिर दूरस्थ क्षेत्रों की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लछमागुडा निवासी समीर मारोती आत्राम (6) घर में सो रहा था, तभी तड़के उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह काफी देर तक जब वह नहीं उठा, तब परिजनों को संदेह हुआ। इसी दौरान घर में जहरीला सांप दिखाई देने पर परिजनों ने तुरंत समीर को पाटण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने आगे के उपचार के लिए गडचांदूर ग्रामीण अस्पताल रेफर कर दिया।

शिरडी से लौटी कार खाई में गिरी, युवती की मौत, दो महिलाएं घायल

हिंदमाता संवाददाता @ बोईसर

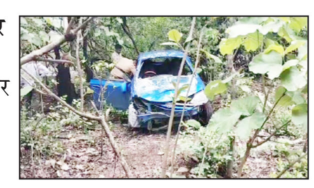

शिर्डी में साई बाबा के दर्शन कर विरार लौट रहे श्रद्धालुओं की कार विक्रमगढ़ के पास भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 27 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

100 फीट गहरी खाई में गिरी कार

विरार की शोरमबाग सोसायटी निवासी भानत परिवार शिर्डी दर्शन के बाद सोमवार को नाशिक-जव्हार-मनोर मार्ग से घर लौट रहा था। विक्रमगढ़ के जांभा गांव के समीप ढलान पर बारिश के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सड़क से करीब 100 फीट नीचे खाई में गिरकर पेड़ों से टकरा गई। हादसे में श्रद्धा संतोष भानत (27) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अपर्णा संतोष भानत (47) और ऐश्वर्या संतोष भानत (26) घायल हो गईं।

स्थानीय लोगों ने बचाई जान

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, राहगीर और विक्रमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। घनी झाड़ियों में फंसी कार से घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से विक्रमगढ़ ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर चालक का नियंत्रण खोने से हादसा होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हिंदमाता एंकर: 34.87 लाख का गुटखा-पान मसाला जब्त

एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 6 होटल-रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल, रेस्तरां और बेकरी संचालकों के एफडीए ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए छह प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर 26 से 28 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 31 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 34.87 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा व अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री, वितरण और परिवहन के मामलों में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही एक प्रतिष्ठान को सील किया गया और तीन वाहन भी जब्त किए गए। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, गलत ब्रांडिंग, भारी गंदगी, रसोई में चूहों और तिलचट्टों का प्रकोप, जंग लगे व खराब रेफ्रिजरेटर, तापमान नियंत्रण व्यवस्था का अभाव, कर्मचारियों की चिकित्सीय जांच न होना और आवश्यक दस्तावेजों की कमी जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इन उल्लंघनों के आधार पर एफडीए ने संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

बिना पर्चे की बिक रही थी नींद की गोलियां

जालना में एफडीए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अल्प्राजोलम की 4,333 रुपए की 1,080 गोलियां जब्त की गई। बिना पर्चे और खरीद बिल के बिक्री का खुलासा होने पर वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स बंद करा दिया गया। साथ ही दो आरोपियों पर एनडीपीएस, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स और बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई।

खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

बीएमसी में इंजीनियरों की कमी

एसआरए में वर्षों से तैनात अभियंताओं को वापस बुलाने की मांग

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

बीएमसी में इंजीनियर के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं, जबकि विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में करीब 20 बीएमसी अभियंता पिछले 8 से 10 वर्षों से झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) में ही कार्यरत हैं। बीएमसी अभियंता विभाग ने इन अभियंताओं को तत्काल बीएमसी में वापस भेजने और उनके स्थान पर अन्य अभियंताओं को दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बीएमसी के अभियंताओं को मूल रूप से दो वर्षों की प्रतिनियुक्ति पर एसआरए भेजा गया था, लेकिन कई अभियंता एक दशक से वहीं कार्यरत हैं। इसके कारण बीएमसी के विभागीय कार्यालयों और अन्य इंजीनियरिंग शाखाओं में अभियंताओं की कमी महसूस की जा रही है।

अन्य अभियंताओं को मौका देने पर जोर

कई स्थानों पर एक ही अभियंता को दो-दो विभागों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड रहा है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले म्हाडा और एसआरए में बीएमसी के द्वितीय श्रेणी अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता कार्यरत हैं। सूत्रों के अनुसार, म्हाडा में कुछ अभियंताओं को स्थायी कर दिया गया है, जबकि एसआरए में भी ऐसी प्रक्रिया शुरू होने की चर्चा है। वर्तमान में एसआरए में बीएमसी के 8 सहायक अभियंता, 10 द्वितीय श्रेणी अभियंता और 2 कार्यकारी अभियंता कार्यरत है। आरोप है कि इनमें से कई अभियंता पदोन्नति की प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेते और आवश्यक दस्तावेज तक जमा नहीं करते। ऐसे में उनकी जगह अन्य अभियंताओं को अवसर देने की मांग जोर पकड़ रही है। इधर, एसआरए प्रशासन ने इन अभियंताओं को स्थायी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। अभियंता वर्ग ने देवेंद्र मुख्यमंत्री फडणवीस से इस प्रस्ताव को मंजूरी न देने की मांग की है। उनका कहना है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनाती रहने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता प्रभावित होती है।

विचार प्रवाह

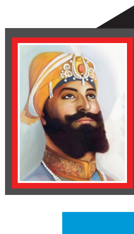

अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की ही ईश्वर मदद करता है।

- गुरु गोबिंद सिंह

संपादकीय

बुजुर्गों की सुविधा-सुरक्षा अनुकूल हों डिजिटल सेवाएं

तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुरक्षा और निर्भरता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है। स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को काफी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है। सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है। मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है। डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें। निस्संदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिजाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे। जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर झल्लाने के बजाय धैर्य से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

आज का इतिहास

■ 1949 - जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ तब त्रावनकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई, 1949 को त्रावनकोर-कोचीन राज्य बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा।

■ 1852 - 1 जुलाई, 1852 को सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रेरे द्वारा सिर्फ.सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए ' सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया।

■ 1960 - घाना अफ्रीका का एक प्रजातंत्र राज्य है, जिसे 1 जुलाई को गणराज्य घोषित किया गया था।

■ 1990 - पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति एवं पश्चिमी जर्मनी की

■ 1990 - पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति एवं पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा को पूर्वी जर्मनी में मान्यता।

■ 1991 - बारसा संधि भंग की गयी।

■ 1994 - रोमान हर्जोग द्वारा जर्मनी के नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण, विश्व कप फुटबाल में आत्मघाती गोल करने वाले कोलंबियाई खिलाड़ी आंद्रेस एस्कोबार की अपने देश में हत्या।

■ 1995 - सं.रा. अमेरिका ने ताईवान के खिलाफ लगाये गये प्रतिबंध को हटाया।

■ 1996 - आस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू।

■ 1997 - ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग चीन को सुपुर्द।

■ 2000 - लार्ड्स के 100वें एतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया।

■ 2003 - समुद्र में सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता।

भारत-फ्रांस सहयोग मजबूत

जी-7 समिट से वैश्विक साझेदारी को नई दिशा, सहयोग की नई शुरुआत

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

फ्रांस की अध्यक्षता में इस साल हुए जी-7 समिट के नाकाम हो जाने की कई वजहें थीं। कई झगड़े, समुद्री व्यापार के रास्तों में रुकावट, ऊर्जा संकट, महामारी का फैलना, ग्लोबल मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन, मदद के तरीकों में रुकावट और विभाजित विश्व की वजह से दांव पर बहुत कुछ लगा था। फिर भी 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में जो हुआ, वह एक साथ आने का दुर्लभ मौका था। नेताओं के बीच सहयोग से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस वादे मुमकिन हो पाए।

जी-7 प्लस की अहम भूमिका

यह सफलता न केवल जी-7 सदस्य देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) के बीच, बल्कि जी-7 प्लस के जरूरी सहयोगी देशों-खासकर भारत और साथ ही ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ भी करीबी तालमेल का नतीजा थी। यूक्रेन, यूएई और कतर को भी अपनी राय देने के लिए नेताओं के समिट में बुलाया गया था। इस अनोखे जी-7 प्लस फार्मेट के जरिये फ्रांस की अध्यक्षता ने न केवल समिट में, बल्कि समिट से पहले तैयारी की प्रक्रिया के दौरान भी पहली बार भारत और सहयोगी देशों के अनुभव और विजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया।

भारत का बढ़ता योगदान

भारत और फ्रांस के जी-7 के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। जी-7 के साथ भारत का जुड़ाव 2003 में फ्रांस के न्योते पर एवियन में शुरू हुआ था। इस साल समिट में भारत की 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवीं भागीदारी थी, जब फ्रांस ने अपनी पिछली अध्यक्षता के दौरान भारत को जी-7 बियारिट्ज समिट में बुलाया था। इस साल जी-7 प्लस में भारत का योगदान सभी मामलों में अहम था, खासकर स्वास्थ्य और डिजिटल टेक्नोलाजी से जुड़ी ग्लोबल चुनौतियों पर। जी-7 नेताओं ने सर्वसम्मति से नौ घोषणाओं को अपनाया और कई को सहयोगी देशों का समर्थन मिला। ये हमारी बड़ी साझा सफलताएं थीं। जी-7 ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, रक्षा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के समर्थन के मामले में मजबूत एकजुटता और संकल्प दिखाया। हमने हाल के महीनों में युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साहस की तारीफ की और उस नई गति पर जोर दिया, जिससे इस आक्रामक युद्ध का न्यायपूर्ण और अंतिम समाधान निकल सकता है।

आर्थिक और वैश्विक संतुलन

हमने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया और होर्मुज से बिना किसी रोक-टोक या टोल के आने-जाने के अधिकार को फिर से दोहराया। हमने लेबनान में तुरंत और मजबूत युद्धविराम की भी पुरजोर मांग की, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन से निपटने के लिए नेताओं ने संतुलित, टिकाऊ और मजबूत विकास का समर्थन किया। उन्होंने माना कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करते हुए, और भविष्य के व्यापार युद्धों और वित्तीय संकटों से बचते हुए आर्थिक नीतियों में सहयोग और समन्वय सभी के हित में है। चूंकि इस बड़ी चुनौती के समाधान में सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए फ्रांसीसी अध्यक्षता ने चीन के साथ रचनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी। चीन ने जी-7 एवियन शिखर सम्मेलन से पहले विकास के लिए एक अभूतपूर्व वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जो 20 वर्षों में पहली बार हुआ।

डिजिटल और एआई सहयोग

डिजिटल तकनीक और एआइ पर, इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट के बाद जी-7 प्लस नेताओं ने बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। हम एआइ सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रहे लोकतंत्रों के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि साझा मानक स्थापित किए जा सकें। जी-7 प्लस सदस्य सुरक्षित और लाभकारी एआइ के इस्तेमाल को तेज करने के लिए प्रमुख कंपनियों के साथ काम करेंगे। इसमें भारत की सर्वम एआइ भी शामिल है।

स्वास्थ्य पर साझा संकल्प

स्वास्थ्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। जी-7 नेताओं और सहयोगी देशों ने इबोला वायरस से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन का संदेश दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के अनुरूप एक अरब डालर से अधिक की धनराशि देने का वादा किया। कैंसर से निपटने पर पहली बार जी-7 का बयान भी जारी हुआ।

सुरक्षा और विकास पर फोकस

नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता को दोहराया, विशेष रूप से मानव विकास और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कार्यान्वित 'फाइनेंस इन कामन' इस दिशा में उपयोगी भूमिका निभाएगा। सभी नेता महत्वपूर्ण खनिजों पर अपनी मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए कुल 195 ठोस सहयोग परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 64 अरब यूरो का संयुक्त निवेश शामिल है। सुरक्षा मुद्दों पर हमने क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी से निपटने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आगे की राह

जी-7 अध्यक्षता अभी समाप्त नहीं हुई है। इन विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए 2026 में कई मंत्री-स्तरीय और कार्य-समूह बैठकें होंगी, जिनमें भारत की अहम भूमिका होगी। ब्रिक्स चेयरमैन के तौर पर भारत और जी20 के चेयरमैन के तौर पर अमेरिका, दोनों ही इन चुनौतियों पर ठोस पहल को आगे बढ़ाने और दुनिया के बीच की दूरियों को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सभी की ओर से तालमेल और रचनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।

आंखनदेखी

कनाडा में फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर कनाडा की शानदार जीत के बाद वैंकूवर में फुटबॉल प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। जीत की खुशी में समर्थकों ने कनाडाई झंडे लहराए, नारे लगाए और सड़कों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला।

बिहार की नई उड़ान

● विकास की रफ्तार पकड़ने का अवसर, विकास की चुनौती

हिंदमाता नेटवर्क @ बिहार

भारत की प्रगति की रेल बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। ऐसा ही एक डिब्बा है-बिहार। जबकि प्राचीन समृद्ध भारत के मानचित्र को देखें तो यही क्षेत्र सबसे संपन्न इलाकों में से एक नजर आएगा। अपनी गहरी सभ्यतागत जड़ों, उर्वर भूमि और प्रतिभाशाली युवाओं की अच्छी-खासी संख्या वाले राज्य को देश में उदारीकरण की बयार के बाद तेज रफ्तार से तरक्की पर सवार होना चाहिए था, लेकिन विरोधाभासों में उलझा यह प्रदेश इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। यह सही है कि पिछले कुछ समय से बिहार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पैठ एवं मानव विकास सूचकांकों के पैमाने पर राज्य अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है।

आर्थिक असमानता

वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 76,490 रुपए रही, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 35 .7 प्रतिशत है। बात केवल प्रति व्यक्ति आय या ऐसे अन्य संकेतकों की ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन की भी है। पटना और उसके आसपास के इलाकों की तुलना में उत्तर एवं पूर्वी बिहार के क्षेत्र कम विकसित हैं। इसका परिणाम पलायन के रूप में सामने आता है। स्थानीय प्रतिभाएं बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर चली जाती हैं और राज्य को उनका समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

पिछड़ने की वजह

स्वतंत्रता उपरांत परिदृश्य की बात करें तो उस समय बिहार की स्थिति बहुत सशक्त थी। अपनी उर्वर मैदानी भूमि के कारण बिहार कृषि उपज का प्रमुख केंद्र था। यहां देश की एक चौथाई चीनी और बागवानी उत्पादों के एक बड़े हिस्से का उत्पादन होता था। डालमिया नगर जैसे शहर आरंभिक औद्योगिक केंद्रों के प्रतीक थे। फिर 1970 से 1990 के दशक में बिहार दिशाहीन राजनीतिक नेतृत्व से त्रस्त रहा। इस नेतृत्व के पास विकास को लेकर न तो कोई समझ थी और न ही दृष्टि। बदहाल कानून एवं व्यवस्था और सरकारी संस्थानों के लचर रवैये ने उद्यमियों के उत्साह पर तुषारापात किया। इसके चलते राज्य के उद्यमियों ने या तो अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए या फिर उन्हें कहीं और ले गए। इस कारण राज्य में निवेश संकुचित होता गया। विकास को गति प्रदान करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र उपेक्षा के शिकार होते गए।

असंतुलित अर्थव्यवस्था

जब तमिलनाडु में चेन्नई और कर्नाटक में बेंगलुरु जैसे शहरों को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप विकसित किया जा रहा था, तब बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे थे। परिणामस्वरूप, बिहार निरंतर पिछड़ता चला गया। वर्तमान में भी बिहार की अर्थव्यवस्था प्रगति के साथ असंतुलन को ही दर्शाती है। राज्य के आर्थिक उत्पादन में सेवा क्षेत्र की सर्वाधिक 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि विनिर्माण और कृषि दोनों 20 प्रतिशत के स्तर पर ही ठिठके हैं। कृषि अभी भी छोटी जोतों, अपर्याप्त सिंचाई, लचर विस्तारित सेवाओं और सीमित भंडारण क्षमताओं के साथ ही बाढ़ एवं सूखे सरीखे जलवायु परिवर्तन के झटकों से उबरने की दृष्टि से कमजोरी जैसे पहलुओं से जूझ रही है।

नीतिगत चुनौतियां

अनुकूल प्राकृतिक परिवेश के लाभ बिहार के उत्पादन में रूपांतरित नहीं हो पा रहे हैं। उत्पादन में महज 20 प्रतिशत योगदान के बावजूद करीब 50 प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ऐसे में, नीतिगत चुनौती फसल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि विविधीकरण, उचित संयोजन, लाजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच के जरिये किसानों की आय बढ़ाने की है। औद्योगिक क्षेत्र में तो मुश्किल की खाई और भी चौड़ी है। विनिर्माण में बिहार की हिस्सेदारी उसकी वास्तविक क्षमता से बहुत नीचे है। यह न भूला जाए कि उद्योगीकरण केवल प्रोत्साहनों के दम पर ही नहीं पनप सकता। उसके लिए निर्बाध एवं भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, सुगम ढुलाई एवं परिवहन, अनुबंधों के प्रवर्तन की व्यवस्था, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच, बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त भूमि, कार्यकुशल कामकाजी आबादी एवं नियमों की सुनिश्चितता भी उतनी आवश्यक है। निवेशक केवल राज्यों के दावों या आकांक्षाओं को ही नहीं देखते, बल्कि उनके लिए धरातल पर वास्तविक स्थिति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है।

पूंजी और सेवा क्षेत्र

पूंजी का प्रवाह सदैव उन्हीं स्थानों की ओर होता है, जहां समग्र तंत्र अनुकूलता लिए होता है। सेवा क्षेत्र में भी राज्य अपनी क्षमताओं को पूरी तरह नहीं भुना पा रहा है।प्रतिकूलताओं के बाद भी बिहार कई स्तरों पर बहुत सहज अवस्था में है। जीडीपी के अनुपात में राज्य का कर्ज 35 से 40 प्रतिशत के दायरे में ही है, जो नियंत्रण में ही कहा जाएगा। ग्रामीण परिवहन एवं कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरी है। विद्युतीकरण एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। हालांकि, औद्योगिक इकोसिस्टम, शहरी बुनियादी ढांचे और लाजिस्टिक्स के साथ ही भंडारण क्षमताओं में सुधार होना शेष है।

असीम संभावनाएं

इन कमियों के बावजूद बिहार में विद्यमान विपुल संभावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में आज चुनिंदा राज्य ही इतनी युवा आबादी वाले हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में आबादी बुढ़ाती जा रही है। कम ही राज्यों के पास बिहार जैसी उपजाऊ भूमि और जल-संसाधनों से समृद्ध कृषि क्षमता मौजूद है। ऐसे राज्य भी अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं जो पूर्वी भारत, नेपाल और गंगा के विस्तृत मैदानी इलाकों के बड़े बाजार के बीच इतने रणनीतिक रूप से अवस्थित हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करे तो बिहार केवल श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्य की छवि को तोड़कर उद्यमों को आकर्षित करने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने का माद्दा रखता है।

नई उम्मीद

अब तक गठबंधन में सहयोगी रही भाजपा के पहली बार नेतृत्व की भूमिका में आने के साथ ही पार्टी के बहुचर्चित डबल इंजन सरकार की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पहले ही ऐसी संकल्पना का लाभ उठाकर आगे बढ़ रहा है और अब इसका फायदा उठाने की बिहार की बारी है। बिहार को अब देश की तेजी से हो रही तरक्की के साथ कदमताल करनी होगी। यहां के लोग बेहतर परिणामों के पात्र हैं।

प्रेरक प्रसंग

परिवार की लाड़ली

गांव के छोटे से बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ लगी थी। हाईवे के किनारे बने उस बस स्टैंड से वाहन तो लगातार गुजर रहे थे, लेकिन लोकल बसें बहुत कम आती थीं। इसी कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। उसी भीड़ में एक परिवार भी खड़ा था। परिवार की तीन पीढ़ियां साथ थीं-दादी, मां-बाप, बेटा और उसकी नई-नवेली दुल्हन। सब अपने-अपने ढंग से समय काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच बेटे ने इंतजार को मजेदार बनाने का एक तरीका खोज लिया। वह सड़क से गुजरते ट्रकों के पीछे लिखे वाक्यों को ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, ताकि परिवार के सभी लोग सुन सकें। कभी किसी ट्रक पर लिखा होता-"मां की दुआ", तो कहीं-"धीरे चलें, सुरक्षित रहें"। लेकिन जब भी कोई रोमांटिक या मजेदार पंक्ति दिखाई देती, वह जानबूझकर पत्नी की ओर देखकर और भी जोर से पढ़ता। नई दुल्हन घूंघट थोड़ा-सा ऊपर उठाती, शर्म से अपने होंठ दांतों तले दबा लेती और सबकी नजरें बचाकर पति को बनावटी गुस्से से देखती। पति को पत्नी के चेहरे पर उभरते ये भाव किसी भी ट्रक की लिखावट से कहीं ज्यादा आकर्षक लगते। इंतजार अब उसे बोझ नहीं, बल्कि एक प्यारा-सा साथ महसूस होने लगा था। तभी संगमरमर से लदा एक भारी-भरकम ट्रक धीरे-धीरे वहां से गुजरा। ट्रक इतना अधिक भरा हुआ था कि उसकी रफ्तार मानो दर्द से कराह रही हो। उसके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था-"परिवार की लाड़ली।"

■ बेटे ने मुस्कराकर कहा, "देखो, परिवार की लाड़ली जा रही है।" इतना कहते हुए उसने प्यार से अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी हंसते हुए बोली, "अरे, इतनी भारी लोडिंग कर रखी है और नाम रखा है 'परिवार की लाड़ली'! कैसी लाड़ली है ये?" उसकी बात सुनकर सास चुपचाप मुस्कराईं। फिर उन्होंने अपने पति और अपनी बूढ़ी सास की ओर एक नजर डाली। कुछ पल के मौन के बाद धीमी आवाज में बोलीं, "बेटी, इतना बोझा लाद रखा है...

■ तभी तो वह परिवार की लाड़ली कहलाती है। वरना..." उनके शब्द अधूरे रह गए। लेकिन उन अधूरे शब्दों में बरसों का संघर्ष, त्याग और एक स्त्री का अनकहा जीवन समाया हुआ था। नई बहू पहली बार अपनी सास के चेहरे को गौर से देख रही थी। उसे लगा, सचमुच हर घर की "लाड़ली" वही होती है, जिसके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उस क्षण ट्रक के पीछे लिखे दो शब्द केवल एक नारा नहीं रहे, बल्कि जीवन का गहरा सत्य बन गए।

राशिफल

मेष- कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। धार्मिक अनुष्ठान पूजा-पाठ इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। मानसिक शांति रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। समय अनुकूल है।

वृषभ- बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। प्रमाद न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक कष्ट संभव है।

मिथुन- कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक काम करने की इच्छा रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। सुख के साधन प्राप्त होंगे। नई योजना बनेगी। तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कर्क- व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। शारीरिक कष्ट संभव है। किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। स्वाभिमान को ठेस लग सकती है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। आय बनी रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है।

सिंह- किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में न आएं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी में मातहतों से कहासुनी हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। कुसंगति से बचें। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।

कन्या- धन प्राप्ति सुगम होगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। शरीर में कमर व घुटने आदि के दर्द से परेशानी हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। शत्रुभय रहेगा।

तुला- धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा। शत्रु पस्त होंगे।

वृश्चिक- किसी वरिष्ठ प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कष्ट व भय सताएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

धनु- कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। दु:खद समाचार प्राप्त हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। थकान व कमजोरी महसूस होगी। आय में निश्चितता रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। राजभय रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

मकर- प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। नौकरी में प्रशंसा होगी। कार्यसिद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी। चोट व रोग से बचें। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति के बहकावे में न आएं। व्यापार ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा।

कुंभ- दूर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर में मेहमानों का आगमन होगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। यश बढ़ेगा।

मीन- व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। निवेश शुभ रहेगा। व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। किसी न्यायपूर्ण बात का भी विरोध हो सकता है। विवाद न करें। कुबुद्धि हावी रहेगी। चोट व रोग से बचें।

अब तक रूठी थी DMK-AAP

SIR पर CJI को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

विपक्षी गठबंधन INDIA के 23 घटक दलों और एक निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने रक्क्रप्रक्रिया को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र भेजा है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 8 जून को हुई बैठक में प्रधान न्यायाधीश को पत्र भेजने का फैसला किया था। इस पत्र पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने आठ जून की बैठक से दूरी बनाई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 8 जून, 2026 को आयोजित इंडिया जनबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने हिस्सा लिया था। निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव संबंधी अन्य मुद्दों पर भारत के प्रधान न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि इसके बाद अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य के हस्ताक्षर वाला संयुक्त पत्र मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश को भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विपक्षी दल 'श्योर' यानी 'सॉलिडैरिटी, यूनिटी एंड रेजीलिएंस' के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम हैं।

पत्र पर किन नेताओं ने किए हस्ताक्षर

सूत्रों के अनुसार, इस संयुक्त पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वाम दलों के नेताओं और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल सहित कई अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इस पत्र पर आम आदमी पार्टी और द्रमुक ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रगतिशील कदम उठाया गया। और हां, आम आदमी पार्टी और द्रमुक ने भी प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में ओब्रायन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह पत्र 'इंडिया' गठबंधन के सभी दलों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

कोर्ट को देखना होगा कि क्या हो रहा

विपक्ष एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, यह पत्र इस विचार पर आधारित है कि जब सभी अन्य संस्थाएं विफल हो जाती हैं, तब भारतीय लोकतंत्र न्यायपालिका की ओर देखता है। विपक्षी नेता ने कहा, "यह पत्र न्यायपालिका की अंतरात्मा को संबोधित करता है। न्यायपालिका को देखना होगा कि आज देश में क्या हो रहा है। जब बाकी सब विफल हो जाए, तो हम किसकी ओर रुख करें?" सूत्रों के अनुसार, पत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया ने विभिन्न राज्यों के लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की तटस्थता और निष्पक्षता को लेकर निरंतर सवाल खड़े कर रहे हैं।

मनरेगा के बकाया और 'जी राम जी' के प्रावधानों पर जवाब दे सरकार: मल्लिकार्जुन खरगे

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' लागू होने से एक दिन पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ग्रामीण भारत से काम का अधिकार छीनने का आरोप लगाया और कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बकाया भुगतान और नई योजना के विभिन्न प्रावधानों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

■ उन्होंने यह दावा भी किया कि मार्च, 2026 तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मनरेगा के तहत 17,144.13 करोड़ रुपए बकाया था और इसमें 7,846.25 करोड़ रुपए की मजदूरी देनदारी शामिल है, जिसका भुगतान अब तक मजदूरों को नहीं किया गया है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एक जुलाई से केंद्र सरकार ने राज्यों पर नई योजना 'विकसित भारत-जी राम जी' लागू की है लेकिन मनरेगा का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कर्नाटक के 700 करोड़ रुपए और झारखंड के 900 करोड़ रुपए सहित कई राज्यों को बकाया राशि नहीं मिली है।

■ खरगे ने कहा, "कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी जबकि नई योजना में राज्यों पर कुल खर्च का 40 प्रतिशत बोझ डाल दिया गया है।" उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों ने भी इस वित्तीय व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नई योजना के तहत खेती के अहम मौसम में 60 दिनों तक काम बंद रखने के प्रावधान का कई राज्यों ने विरोध किया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे किसानों और ग्रामीण मजदूरों पर थोप रही है।

■ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 125 दिनों के रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश पर 20,037 करोड़ रुपये और बिहार पर 15,939 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कम से कम पांच राज्यों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। खरगे के मुताबिक, कांग्रेस शुरू से ही 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग करती रही है जबकि बिहार ने दैनिक मजदूरी 255 रुपये से बढ़ाकर 413 रुपये और जम्मू-कश्मीर ने 272 रुपये से बढ़ाकर 311 रुपये करने की मांग की है।

खरीफ फसलों की बुआई में 22.7% की कमी आई

■ खरगे ने दावा किया कि जून में सामान्य से 42 प्रतिशत कम बारिश हुई है और खरीफ फसलों की बुआई में 22.7 प्रतिशत की कमी आई है। उनका कहना था कि 300 से अधिक जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं और ग्रामीण भारत में आजीविका का संकट गहरा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में मनरेगा को खत्म करना क्या मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबों पर हमला नहीं है?

हम पाकिस्तान में नहीं... पीओके के कश्मीरियों ने कर दिया ऐलान

अब क्या करेंगे शाहबाज और मुनीर?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

हम पाकिस्तान में नहीं हैं... ये कहना है पीओके में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों का। दरअसल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में सरकार विरोधी आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया है। वे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खुलकर कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और चेतावनी दी कि अगर इस्लामाबाद खाद्य आपूर्ति रोकना जारी रखा तो वे अन्य रास्ते' अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि POK के कश्मीरी किसी भी तानाशाह (शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर) को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल, रावलकोट के ईदगाह मैदान में जारी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार नागरिकों को सामूहिक सजा दे रही है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेता सरदार अमन खान ने कहा कि हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है। आपको हमारी जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपूर्ति इसी तरह रही तो स्थानीय लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अन्य विकल्प तलाशने पड़ेंगे।

कई दिनों से पीओके में प्रदर्शन

बता दें कि यह आंदोलन पिछले कई दिनों से पीओके के विभिन्न इलाकों में जारी है। जेएएसी के नेतृत्व में लोग सस्ते राशन, बिजली, पानी, बेहतर सड़कें, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इस महीने की शुरुआत में जेएएसी पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाने के बावजूद आंदोलन न केवल जारी है, बल्कि तेज भी होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हालिया विवादास्पद टिप्पणी का जवाब मानी जा रही है। आसिफ ने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को 'वास्तविक कश्मीरी नहीं' बताया था, जिससे पूरे पीओके में भारी आक्रोश फैल गया।

बाजारों में राशन की भारी कमी

वहीं, इस्लामाबाद ने पूरे आंदोलन को 'राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा' बताकर दबाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से खाद्यान्न, ईंधन और दवाइयों की आपूर्ति जानबूझकर रोकी जा रही है, ताकि प्रदर्शनकारी थककर हार मान लें। स्थानीय बाजारों में राशन की भारी कमी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं सरदार अमन खान सहित जेएएसी के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी एजेंसियों ने आतंकवाद विरोधी प्रावधानों के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हैं।

अब तक 22 लोगों की मौत

जून के पहले सप्ताह से ही पीओके के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये प्रतिबंध आंदोलन की तस्वीरों, वीडियो और सच्ची खबरों को बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। लगभग दो सप्ताह से चले आ रहे गतिरोध और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। खाद्य पदार्थों की कमी से पीओके के कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

जनरल धीरज सेठ बने भारतीय सेना के नए प्रमुख, संभाला कार्यभार

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को नए सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनके नाम पश्चिमी मोर्चे पर सेना की दो अभियानगत सैन्य कमान के नेतृत्व की विशिष्ट उपलब्धि दर्ज है। जनरल सेठ ने 13 लाख सैनिकों वाली सेना की कमान ऐसे समय में संभाली है जब वह सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनरल सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है जो सशस्त्र बलों में 40 साल से अधिक के शानदार करियर के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए।

सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां गंभीर

जनरल सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में 'आर्मर्ड कोर' में शामिल किया गया था। 31वें सेनाध्यक्ष (सीओएएस) बनने से पहले उन्होंने उप सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दी थी। जनरल सेठ ने ऐसे समय में सेनाध्यक्ष का पद संभाला है जब वैश्विक भू-रणनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। प्रौद्योगिकी में तरक्की और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप की वजह से सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और भी गंभीर होती जा रही हैं।

युद्ध-क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान

रक्षा मंत्रालय ने पहले बताया था कि सैन्य कमांडर के पद पर पदोन्नति के बाद उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड (जयपुर में स्थित) और सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर काम किया। इस तरह उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर दो अभियानगत कमान का नेतृत्व करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। लगभग चार दशकों के अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने अभियानगत, रणनीतिक, दक्षता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया जिससे भारतीय सेना की युद्ध-क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

उग्रवाद-विरोधी अनुभव भी शामिल

सेना मुख्यालय में रणनीतिक योजना और दक्षता विकास जैसे अहम विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण की दिशा, दक्षता विकास की रूपरेखा और सेना की संरचना से जुड़ी दीर्घकालिक पहलों को आकार दिया। एक अप्रैल को उप सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्ति से पहले वह पुणे स्थित सदर्न कमांड के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में इस विशिष्ट कमान ने पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अभियान के लिए उच्च स्तर पर तत्परता बनाए रखी। लगभग चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने विविध भूभागों और संघर्ष की परिस्थितियों में शानदार अभियानगत अनुभव हासिल किया जिसमें उग्रवाद-विरोधी अनुभव भी शामिल है।

आतंकवाद-रोधी बल का नेतृत्व शामिल

अधिकारी ने अलग-अलग अभियानगत माहौल में हर स्तर पर कमान का नेतृत्व किया है। उनकी कमान संबंधी जिम्मेदारियों में रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे पर एक आर्मर्ड ब्रिगेड तथा जम्मू कश्मीर में एक आतंकवाद-रोधी बल का नेतृत्व शामिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने सेना के प्रमुख 'स्ट्राइक फॉर्मेशन' में से एक 'सुदर्शन चक्र कोर' की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग, दिल्ली एरिया' के रूप में काम किया और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की अहम सैन्य गतिविधियों और औपचारिक जिम्मेदारियों को संभाला।

दक्षता विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा

उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्टाफ और रणनीतिक पदों पर भी कार्य किया है, जिनका 'अभियानगत योजना, सुरक्षा बल प्रबंधन और दक्षता विकास' पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जनरल सेठ का योगदान अभियानगत आवश्यकताओं को नयी प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्धक्षेत्र की जरूरतों के साथ जोड़ने में बहुत अहम रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 'हायर कमांड कोर्स' और 'नेशनल डिफेंस कॉलेज' से स्नातक होने के अलावा जनरल सेठ ने पेरिस में प्रतिष्ठित 'कमांड एंड स्टाफ कोर्स' भी किया जो उनकी व्यापक रणनीतिक सोच और समकालीन सैन्य मामलों की समझ को दर्शाता है।

दिल्ली-महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत पांच राज्यों में SIR शुरू

किन-किन बातों का रखें ध्यान?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

चुनाव आयोग का वोटर वेरिफिकेशन अभियान, जिसे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) कहा जाता है, मंगलवार 30 जून से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गया है। रक्क्रके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) वेरिफाई करने के लिए घर-घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं।

राज्यों में क्यों हो रहा SIR?

SIR की प्रक्रिया अगले एक महीने तक चलने वाली है। इस अभियान के दौरान BLO, 30 जून से 29 जुलाई के बीच हर घर जाएंगे और मौजूदा वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और उनसे भरे हुए फॉर्म इकट्ठा करेंगे। अभियान के तहत इस वेरिफिकेशन का मकसद यह पक्का करना है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ योग्य नागरिक ही रहें और अयोग्य लोगों के नाम हटा दिए जाएं। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया जाएगा और फिर 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

किन-किन बातों का रखें ध्यान?

जब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके घर आएं तो आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना चाहिए, एक कॉपी BLO को वापस देनी चाहिए और एक एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए, जिससे आपके पास फॉर्म भरने का प्रूफ हो। अगर आपका घर बंद है, तो BLO एन्यूमरेशन फॉर्म वहीं छोड़ देंगे और भरा हुआ फॉर्म लेने के लिए कम से कम तीन बार आएंगे। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ने साफ तौर पर बताया है कि एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है और पिछली SIR में नाम भी नहीं है, तब आप अपने माता-पिता या दादा-दादी (अपने मायके/पैतृक परिवार) की जानकारी दे सकते हैं, ससुराल वालों की नहीं।

क्या ऑनलाइन भरा जा सकता है फॉर्म?

एन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय, मौजूदा वोटर्स को पिछली 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) से जुड़ी जानकारी देनी होगी। आप पुरानी वोटर लिस्ट से डिटेल जानने के लिए EPIC (वोटर ID) नंबर, अपना नाम या अपने पोलिंग स्टेशन से जानकारी हासिल कर सकते हैं। न तो आपका नाम वोटर लिस्ट में हो और न माता-पिता का नाम, तब क्या करें? आप एन्यूमरेशन फॉर्म में उनके नाम लिखवा सकते हैं। बाद में आपसे आपकी बात को सत्यापित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स (सहायक दस्तावेज) देने के लिए कहा जा सकता है।

राम मंदिर मामले पर पीएम मोदी की 'चुप्पी' करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है: जयराम रमेश

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'चुप्पी' देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर 'सीधा आघात' है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा 'एक्स' पर किए एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि श्रीराम मंदिर में कथित 'लूट' पर प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को जगह दी।

■ रमेश ने यह भी दावा किया कि बाद में पूरे ट्रस्ट को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी 'चुप्पी तोड़ने' की मांग की। अजय राय ने 'एक्स' पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन-पूजन के लिए जाने से पहले उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की 'तानाशाही' करार दिया। राय ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन-पूजन के लिए जाने वाला था। मैं अयोध्या पहुंचा ही था कि भाजपा सरकार इतनी डर गई कि पुलिस मुझे होटल से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठाकर ले जा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन घोटालों और चढ़ावे की चोरी में शामिल लोगों को 'राम भक्तों के आने से डर' लग रहा है। उन्होंने भाजपा पर 'आस्था पर पहरा देने' का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई को 'कायरतापूर्ण' और 'निंदनीय' बताया। राय ने कहा कि हम न रुकेंगे, न झुकेंगे।

ऑस्ट्रिया में शिक्षा से लेकर करियर तक मिलेगा सहयोग

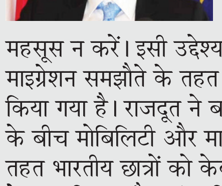

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत में ऑस्ट्रिया के राजदूत रॉबर्ट ज़िशग ने कहा है कि ऑस्ट्रिया चाहता है कि वहां उच्च शिक्षा के लिए आने वाले भारतीय छात्र खुद को अकेला महसूस न करें। इसी उद्देश्य से भारत-ऑस्ट्रिया मोबिलिटी और माइग्रेशन समझौते के तहत एक विशेष ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजदूत ने बताया कि 2023 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मोबिलिटी और माइग्रेशन पर समझौता हुआ था। इसके तहत भारतीय छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के लिए भी पहले से तैयार किया जाता है।

■ इस कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रिया में पहले से पढ़ रहे भारतीय छात्र नए छात्रों का स्वागत करेंगे। वे उन्हें स्थानीय संस्कृति, रहन-सहन और शहर से परिचित कराएंगे, ताकि वे शुरुआत से ही सहज महसूस करें। राजदूत ने कहा कि कई छात्र पहली बार विदेश जाते हैं और वहां अकेलापन महसूस करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क उपलब्ध कराना है। यह पहल Technical Universities Austria के तहत संचालित की जा रही है। इसमें वियना, ग्राज और लेओबेन के तकनीकी विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत की ओर से आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बेंगलुरु सहित कई प्रमुख तकनीकी संस्थान इसमें सहयोग कर रहे हैं। रॉबर्ट ज़िशग ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश शिक्षा, कौशल, रोजगार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रित और सुव्यवस्थित प्रवासन (Migration) दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है और इसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है।

ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बलूचिस्तान को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता ओमर करीम Aomar Karim ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई से 3 जुलाई तक लंदन में ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) के बाहर शांतिपूर्ण तीन दिन की भूख हड़ताल करेंगे। यह प्रदर्शन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के Balochistan में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, जबरन गुमशुदगी, मनमानी गिरफ्तारियों और बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना है।

■ उन्होंने लोकतांत्रिक देशों से जबरन गुमशुदगी रोकने, कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जवाबदेही तय करने और सभी बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की। तीन दिवसीय भूख हड़ताल का समापन 3 जुलाई को शाम 5:30 बजे FCDO के बाहर एक रैली के साथ होगा। आयोजकों ने ब्रिटेन में रहने वाले बलूच समुदाय, सांसदों, पत्रकारों, वकीलों, छात्रों, ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकार संगठनों से इसमें शामिल होकर समर्थन देने की अपील की है।

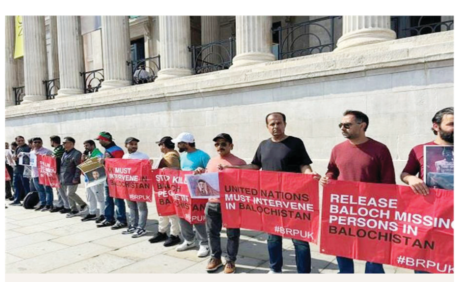

■ इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दामहरंग बलूच और सिबघतुल्लाह शाहजी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। ओमर करीम ने ब्रिटेन सरकार से मांग की है कि वह सार्वजनिक रूप से इन सजाओं की निंदा करे और पाकिस्तान से महरंग बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी तथा अन्य हिरासत में रखे गए बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की अपील करे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से भी बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। करीम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकारी संस्थाएं, सेना, राजनीतिक नेतृत्व और न्यायपालिका बलूच समुदाय के साथ गंभीर अन्याय कर रहे हैं।

यूपी फतह के लिए नितिन नबीन ने बनाया प्लान!

लखनऊ में होने जा रही बीजेपी और आरएसएस की बैठक; सीएम योगी भी होंगे शामिल

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरूआती महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 3 और 4 जुलाई को राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। जनवरी 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद, नितिन नबीन की उत्तर प्रदेश में यह पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक है।

शीर्ष नेतृत्व और संघ के साथ महामंथन

दो दिवसीय इस दौरे के दौरान नबीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ समन्वय बैठक आयोजित करेंगे। इन बैठकों में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ-साथ भाजपा की नवनियुक्त राज्य टीम भी शामिल होगी। सूत्रों का कहना है कि नबीन इस अवसर का उपयोग नई टीम को आगामी मिशन उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों और रणनीतियों से अवगत कराने के लिए करेंगे। खबर के अनुसार, यह समन्वय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच बेहतर तालमेल बिठाने की एक कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह का फीडबैक अभ्यास अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया था।

ओबीसी कार्ड पर होगी चर्चा

समाजवादी पार्टी द्वारा पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों के बीच भाजपा ने भी अपनी पलटवार की रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा का मुख्य फोकस उन ओबीसी उपजातियों पर है, जो राज्य की सत्ता तक पहुंचने के लिए निर्णायक भूमिका निभाती हैं। संगठन स्तर पर तैयारी इतनी पुख्ता है कि बूथ सत्यापन का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण चुनाव से ठीक एक महीने पहले आयोजित करने की योजना है। नबीन स्वयं जमीनी कार्यकताओं से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

विवादों के साये में चुनावी समीक्षा

इसके अलावा, भाजपा की यह समन्वय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य की राजनीति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा चोरी घोटाले को लेकर गरमाई हुई है। विपक्षी दलों, विशेषकर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। हाल ही में एक विशेष जांच समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और की गई गिरफ्तारियों के बाद उपजे राजनीतिक माहौल के बीच भाजपा अपनी भावी रणनीति की समीक्षा करेगी।

2 करोड़ की जमीन, 18 करोड़ की डील और 'शीश महल'

अयोध्या के चिंटू तिवारी की आलीशान हवेली पर विवाद

हिंदमाता नेटवर्क @ अयोध्या

अयोध्या में राम मंदिर जुड़े कई विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। दान चोरी के अलावा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम चर्चा में है। राम मंदिर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी का एक आलीशान महलनुमा घर बना है। सोशल मीडिया पर इस घर के वीडियो काफी वायरल हुए थे। कई लोगों ने इसे जमीन सौदे से जोड़कर सवाल उठाए थे। विवाद की शुरूआत साल 2021 में हुई एक जमीन डील से हुई थी। आरोप लगाया गया था कि रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी और सुल्तान अंसारी ने अयोध्या के बाग बिजेसी इलाके में एक जमीन का टुकड़ा कुसुम पाठक और उनके पति से करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद महज 10 मिनट के अंदर इसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को करीब 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस समय सवाल उठाया गया कि जब ट्रस्ट सीधे किसानों से जमीन खरीद सकता था, तो इतनी जल्दी और अधिक कीमत पर जमीन क्यों खरीदी गई। इस जमीन सौदे को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप यह भी लगाया गया कि इस अवैध कमाई का इस्तेमाल रवि मोहन ने अपने लिए आलीशान महलनुमा घर बनाने में किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुद्दे को उठाया था। संजय सिंह ने जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे। दावा किया था कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंदे के पैसे की हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा था कि इन दस्तावेजों को रक्ष्ळ और जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। हालांकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। चंपत राय ने इसे नियमानुसार बताया था।

- उन्होंने कहा था कि जमीन का सौदा बाजार दर और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किया गया था। ट्रस्ट की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिस जमीन को खरीदा गया, उसका एग्रीमेंट पहले ही कई वर्षों से चल रहा था। इसलिए तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया गया। इस मामले में सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की थी।
- इसके बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई। इस विवाद में अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में आया था। इसकी वजह जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। विवादित जमीन की रजिस्ट्री में ऋषिकेश उपाध्याय ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
- उनके गवाह बनने के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरह के विवादित और करोड़ों रुपये के जमीन सौदे में गवाह की भूमिका क्यों निभाई।

शॉर्ट स्टोरी

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, अब जंतर-मंतर बनेगा अगला मोर्चा

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की तेरहवीं के मौके पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन तेज करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का ऐलान किया गया। प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉ। अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। तीनों वक्ताओं ने कहा कि जब तक भरत तिवारी मामले में न्याय नहीं मिलता, तब तक कानूनी लड़ाई और आंदोलन दोनों लगातार जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आंदोलन के तहत देशभर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के जरिए लोगों का समर्थन जुटाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनका कहना था कि मामले में हुई न्यायिक जांच पर कई सवाल हैं और इस पूरे प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अनिल मिश्रा ने मांग की कि इस मामले में एसपी समेत सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच की निगरानी किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका जांच के दायरे में आती है, उन्हें पहले निलंबित किया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

मोहम्मद रेहान पर मोमोज के बहाने ब्लैकमेल का आरोप

हिंदमाता नेटवर्क @ गया

बिहार के गया जिले में एक मोमो विक्रेता की घिनौनी हरकत सामने आई है। वो फ्री में मोमोज खिलाकर युवतियों को पहले अपने प्रेमजाल में फंसाता था, फिर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता था। अब तक शहर की 10 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिल चुके हैं। इस मोमो वाले ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, इसका पूरा पता लगने से पहले ही वह फरार हो गया। इस मामले में पुलिस की नींद तब खुली, जब आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस पूरी घटना को मोमोज विक्रेता मोहम्मद रेहान ने अंजाम दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी वीडियो एक धार्मिक स्थल पर बनाए गए हैं। इस बीच, जिले के बांकेबाजार थाना क्षेत्र स्थित बांकेधाम पहाड़ी के एक धार्मिक स्थल पर बनाए गए कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोमोज दुकान संचालक रेहान के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) व तकनीकी सेल की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस को अब तक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित 10 वीडियो मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इन वीडियो में एक ही युवक अलग-अलग युवतियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जांच में एक नाबालिग पीड़िता की पहचान हुई है, जिसके आधार पर वीडियो बनाए जाने के स्थान, परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी रेहान गया छोड़कर मुंबई फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

पूर्णिया:पहली बारिश में ही खुली 'अमृत भारत स्टेशन' की पोल

हिंदमाता नेटवर्क @ पूर्णिया

कहते हैं कि किसी भी निर्माण कार्य की असली परीक्षा पहली बारिश होती है। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए गए करीब 21.5 करोड़ रुपये के पुनर्विकास की भी पहली परीक्षा हुई, लेकिन यह परीक्षा निर्माण एजेंसी के लिए कई सवाल छोड़ गई। उद्घाटन से पहले हुई हल्की बारिश में ही स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म की छत से कई जगह पानी टपकने लगा। इसका वीडियो सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार अहले सुबह हुई हल्की बारिश के दौरान यात्रियों ने देखा कि नवनिर्मित प्लेटफॉर्म की छत से कई स्थानों पर लगातार पानी फव्वारे की तरह गिरने लगा, मानों किसी ने नल खोल दिया हो। यात्रियों को भीगने से बचने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। जिस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। उसी स्टेशन की छत उद्घाटन से पहले ही टपकने लगी, जिससे लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने तंज कसते हुए कहा, अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन तो अभी होना बाकी है, लेकिन छत ने पहले ही अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। लोगों का कहना है कि अगर हल्की बारिश में ही यह स्थिति है, तो पूरे मानसून में हालात क्या होंगे। बनमनखी जंक्शन, जो कोसी-सीमांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, उसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 21.5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इस स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, विशाल पार्किंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली और स्थानीय कला-संस्कृति पर आधारित आकर्षक सजावट जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा उद्घाटन से पहले इस स्टेशन का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं।

घर के बाहर सो रहे परिवार को गैस टैंकर ने रौंदा

पिता-बेटे की मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शिकोहाबाद क्षेत्र के मैनपुरी रोड स्थित मोहम्मदपुर गांव में तेज रफ्तार गैस टैंकर सड़क किनारे घर के बाहर सो रहे परिवार पर चढ़ गया। हादसे में पिता कासिम अली और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह तड़के अरांव रोड की ओर से आ रहा गैस टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया। प्रारंभिक आशंका है कि चालक को झपकी आने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया। बेकाबू टैंकर सीधे सड़क किनारे सो रहे परिवार पर चढ़ गया। इसके बाद टैंकर पास में खड़े एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक मकान में जा घुसा। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। जेसीबी मशीन की सहायता से टैंकर को हटाया गया, जिसके बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

योगी को घेरने चले थे विरोधी, लेकिन उलटी पड़ गई बाजी

जानिए अयोध्या चंदा चोरी केस में कैसे बदला पूरा खेल

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले के खुलासे के बाद भाजपा की आंतरिक राजनीति से लेकर प्रदेश के रणनीतिक मोर्चे पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस मामले में जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट न सिर्फ प्रदेश में भाजपा का भविष्य तय करेगी बल्कि इस रिपोर्ट के पन्ने योगी की ताकत को बढ़ाने या घटाने का भी कार्य करेंगे। यह माना जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को पहले इस लक्ष्य के साथ ही उठाया गया था कि इसकी लपेट में राज्य के सीएम योगी आएंगे। लेकिन इसकी जगह इसकी आंच भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पर पड़ने लगी। लोगों के बीच यह धारणा बनी कि इस मंदिर का निर्माण भाजपा का लक्ष्य रहा है। इसके ट्रस्ट में अधिकतर संघ व विहिप के लोग हैं। ऐसे में योगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह भी चर्चा रही कि योगी ने दिवाली और अन्य अवसर पर अयोध्या में बड़े आयोजन कर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का ही कार्य किया था। लेकिन भाजपा नेताओं ने यहां पर चंदा चोरी पर अंकुश नहीं लगाया।

सीएम का मास्टरस्ट्रोक केंद्र पर भी पड़ रहा भारी

जबकि पीएम मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख रहे हैं। वहीं, संघ के कार्यकर्ता चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के कर्ताधर्ता रहे हैं। इस मामले में यूपी के सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक यह रहा कि जब उन्होंने देखा कि इस मामले की वजह से जनता के बीच देश भर में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने बिना एफआईआर किए ही एसआईटी गठित कर दी।

एसआईटी रिपोर्ट तय करेगा योगी का कद

हालांकि यूपी के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है। यह उनका राजनीतिक कद बढ़ाने या घटाने का कार्य करेगा, क्या ड्राइवर, चपरासी पकड़े जाएंगे या फिर बड़ी मछलिया भी फंसेगी। इससे आगे की राजनीति तय होगी। अगर यूपी पुलिस और एसआईटी ने कुछ बड़े नामों को गिरफ्त में लिया तो योगी का कद बढ़ना तय है। ऐसा नहीं होने पर उन पर भी मिलीभगत कर आरोपियों को छोड़ने का दाग लग सकता है। नेता ने कहा कि इस समय योगी सबसे सुरक्षित और मजबूत स्थिति में हैं।

मानव तस्करी करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार

हिंदमाता नेटवर्क @ आजमगढ़

मानव तस्करी और नाबालिग लड़की को बेचने के मामले में रौनापार पुलिस ने लंबे समय से भागी हुई महिला आरोपी पुष्पा (35) निवासी नकीब खोजौली रौनापार को सपहा पाठक तिराहा, चिलबिली रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर बेचने के मामले में सह-आरोपी होने का आरोप है। थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि 12 अक्तूबर 2024 को रौनापार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर उसकी नाबालिग बहन को सुनील यादव द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर प्राथमिकी में मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। जांच में अनिल यादव, पुष्पा, श्रीमती देवी और एक अज्ञात खरीदार का नाम सामने आया। इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील यादव और अनिल यादव को तीन दिसंबर 2024 और सह-अभियुक्ता श्रीमती देवी को पांच जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

काशी विश्वनाथ धाम पहुंचीं डिंपल यादव: मंगला आरती में हुई शामिल

अखिलेश यादव के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना

हिंदमाता नेटवर्क @ वाराणसी

धर्मनगरी वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने अपने परिवार के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर प्रातःकालीन प्रसिद्ध मंगला आरती में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद सांसद डिंपल यादव ने भगवान शिव से अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु और जनसेवा के उनके संकल्प को निरंतर शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही प्रदेश और देश में सुख, शांति, समृद्धि तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी कामना की।

बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर

मंगला आरती के दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में डिंपल यादव पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल हुईं। उनके मंदिर पहुंचने पर वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उनका अभिवादन किया और बाबा विश्वनाथ के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा।

बनारसी मिठाई का लिया स्वाद

बता दें कि दर्शन के बाद डिंपल यादव ने अपने परिवार के साथ चौक स्थित एक प्रसिद्ध मिष्ठान की दुकान पर बनारसी मिठाई का स्वाद भी लिया। इस दौरान सपा के पूर्व पार्षद रंजना यादव और उनके पति मनीष यादव ने डिंपल यादव को अंग वस्त्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।

धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लिया भाग

डिंपल यादव ने इस दौरान न केवल धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में भी शामिल हुईं। बता दें कि 1 जुलाई को अखिलेश यादव को जन्मदिन मनाया जाएगा।

नाले में शव, खेत में सिर.. मऊ में फोरलेन किनारे दिव्यांग की सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी

हिंदमाता नेटवर्क @ मऊ

मऊ जिले की घोसी कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर मिजार्पुर नवापुरा गांव में मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे फोरलेन के किनारे नाले में युवक का सिर कटा शव मिला। वहां से 100 मीटर दूर खेत में सिर पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओजी टीम ने करीब एक घंटे तक आसपास साक्ष्य इकट्ठा किया। शव का एक हाथ भी कटा था। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की दोपहर से ही हवा चलने पर दुर्गंध आ रही थी। मंगलवार की सुबह दुर्गंध तेज होने पर पास जाकर देखा तो युवक का सड़ा गला शव पड़ा था। शरीर पर जंगली जानवर या कुत्तों के नोचने और काटने जैसे निशान थे। 100 मीटर दूर मिला सिर खून से सना हुआ था और काफी हद तक सड़ चुका था। पुलिया के ऊपर फोरलेन पर लगी स्टील बैरिकेडिंग के पास खून के निशान मिले। घटनास्थल से एक सफेद गमछा, शराब की खाली बोतलें, गुटखा के रैपर और एबी लिखा एक स्टीकर भी बरामद हुआ है जिन्हें पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर लेकर जांच शुरू कर दी है। शव के गले में माला और लॉकेट मिलने से पुलिस को उसकी पहचान होने की उम्मीद है। एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में युवक के दिव्यांग होने का जिक्र नहीं है। हालांकि प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को शव की शिनाख्त के लिए सूचना दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने युवक की अनुमानित उम्र 40 से 42 साल तक बताई है। बताया कि संभवतः युवक की मौत तीन दिन पहले हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। पहचान के लिए आसपास के जिलों की डीसीआरबी और थानों से संपर्क करके पता किया जा रहा है। ताकि इससे मिले जुले व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज होने पर पहचान में आसानी होगी।

हिंदमाता एंकर: जब जांच टीम आयुष मलिक के घर पहुंची तो वहां से एक बड़ा चाकू और एक निजी डायरी बरामद हुई, डायरी पर अंग्रेजी में आई एम ऑन मिशन लिखा मिला

'आई एम ऑन मिशन' से लेकर 2047 पासवर्ड तक, फिर से हिंदू धर्म अपनाने वाले आयुष मलिक केस में मिले नए सुराग

हिंदमाता संवाददाता @ शामली

यूपी के शामली धर्मांतरण मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए तथ्य और सवाल सामने आ रहे हैं। आयुष मलिक के फिर से हिंदू धर्म अपनाने के बाद एक ई-मेल आईडी का पासवर्ड, घर से बरामद एक डायरी, उस पर लिखे कुछ शब्द और फरार बताए जा रहे एक मौलवी की तलाश है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन सभी पहलुओं को जोड़कर यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि मामला केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित था या इसके पीछे कोई व्यापक नेटवर्क सक्रिय था। हालांकि, इन बिंदुओं पर जांच अभी जारी है।

जांच में सामने आया '2047' पासवर्ड

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान जब आयुष मलिक से उसकी ई-मेल आईडी का पासवर्ड पूछा गया तो उसने जो बताया उसमें 2047 भी था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस पासवर्ड के महत्व की पड़ताल शुरू की। सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस संख्या का किसी विचारधारा, संगठन या किसी अन्य संदर्भ से कोई संबंध है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष जारी नहीं किया है।

आखिर क्यों चर्चा में है 2047

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य एजेंसियों की पूर्व जांच में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से जुड़े कुछ दस्तावेजों में 2047 का उल्लेख सामने आया था। इसी वजह से शामली मामले में भी इस पासवर्ड की जांच की जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शामली धर्मांतरण मामले में अब तक किसी आरोपी का पीएफआई से संबंध अदालत में सिद्ध नहीं हुआ है और पुलिस ने भी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां केवल उपलब्ध तथ्यों का सत्यापन कर रही हैं।

तलाशी में क्या मिला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब जांच टीम आयुष मलिक के घर पहुंची तो वहां से एक बड़ा चाकू और एक निजी डायरी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि डायरी के एक पन्ने पर अंग्रेजी में आई एम ऑन मिशन लिखा मिला। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित नोट का संदर्भ क्या था और इसका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल पुलिस ने डायरी की सामग्री पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

चांदनी और उसके पिता गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में एक मौलाना सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी।

फरार मौलवी की तलाश जारी

जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है। पुलिस एक ऐसे मौलवी की तलाश कर रही है, जिसका नाम इस मामले की जांच में सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को आशंका है कि वह उत्तर प्रदेश छोड़कर अंडमान या चेन्नई क्षेत्र में कहीं छिपा हो सकता है। उसकी तलाश के लिए विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने उसकी पहचान और लोकेशन को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

किन सवालों के जवाब तलाश रही है

1- ई-मेल पासवर्ड 2047 का वास्तविक संदर्भ क्या है।

2- डायरी में लिखे आई एम ऑन मिशन का क्या अर्थ था।

3- फरार मौलवी की भूमिका क्या रही।

4- धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ या किसी साजिश के तहत।

5- डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों से क्या नए तथ्य सामने आते हैं।

19 साल बाद पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे व्लादिमीर पुतिन

क्यों लिया ये फैसला?

हिंदमाता नेटवर्क @ मॉस्को

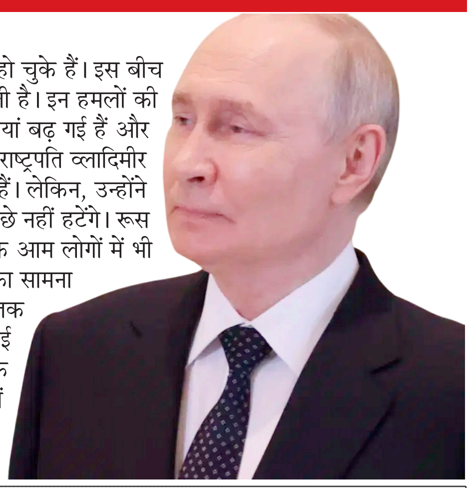

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के कई बड़े शहरों तक पहुंच बना ली है। इन हमलों की वजह से रूस में ईंधन की कमी, इंटरनेट बंद होने जैसी परेशानियां बढ़ गई हैं और आम लोग भी अब युद्ध से परेशान होने लगे हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से देश में परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन, उन्होंने साफ कर दिया कि वह युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचने की वजह से अब रूस के आम लोगों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है, क्योंकि लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। सितंबर में रूस में संसदीय चुनाव होने हैं। ऐसे में क्रेमलिन के सामने चुनौती है कि वह जनता की नाराजगी को कैसे संभाले। लोगों का गुस्सा फिलहाल सीधे पुतिन पर नहीं, बल्कि सत्ता में मौजूद यूनाइटेड रशिया पार्टी पर निकल रहा है।

पुतिन पर भरोसा हुआ कम

रूस की सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड रशिया की लोकप्रियता लगातार घट रही है। पार्टी की समर्थन रेटिंग करीब 30 प्रतिशत के आसपास बताई जा रही है। इसके बावजूद इस बार पार्टी ने खुद को खुलकर राष्ट्रपति पुतिन से जोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी की बैठक में पुतिन के साथ होना ही न्यूनतम जिम्मेदारी है जैसे पोस्टर लगाए गए और 2007 के बाद पहली बार खुद को राष्ट्रपति की पार्टी बताया गया। पार्टी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पुतिन के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, सर्वे बताते हैं कि लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। क्रेमलिन से जुड़े सर्वे संस्थान एफओएम के मुताबिक, पुतिन पर भरोसा घटकर 69 प्रतिशत पर आ गया है, जो 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद सबसे कम स्तर माना जा रहा है।

लोगों की नाराजगी बढ़ी

रूस में इंटरनेट बंद होने और ईंधन की कमी जैसी समस्याओं ने लोगों की नाराजगी और बढ़ा दी है। हालांकि, वहां खुलकर सरकार का विरोध करना आसान नहीं है, क्योंकि असहमति जताने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता रहा और रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में सरकार के लिए हालात संभालना और मुश्किल हो सकता है।

प्रस्ताव से किया मना

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूक्रेन ने कई बार सीमित युद्धविराम का प्रस्ताव दिया, ताकि लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले रुक सकें। लेकिन, पुतिन ने इसे नहीं माना है। उनका मानना है कि अगर उन्होंने कोई समझौता किया, तो रूस कमजोर दिखाई देगा और युद्ध में उसकी बढ़त खत्म हो सकती है। इसलिए वे किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि फिलहाल शांति की संभावना भी कम दिखाई दे रही है।

पाकिस्तान के जिस जेल में बंद हैं इमरान खान, वहां से 14 कैदी फरार

हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाने वाली अदियाला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। यही वह जेल है, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले कई महीनों से बंद हैं। लेकिन, इस बार चर्चा इमरान खान की नहीं, बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों की हो रही है। खबर है कि इसी हाई-सिक्योरिटी जेल से 14 कैदी फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फरार कैदियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अदियाला सेंट्रल जेल को रावलपिंडी जिला जेल भी कहते हैं, इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि 14 कैदियों को अदालत में पेशी के बाद से अदियाला जेल ले जाया जा रहा था। इसी बीच मौके की ताक में बैठे सभी कैदी पुलिस वैन से फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों ने जेल की सुरक्षा में मौजूद खामियों का फायदा उठाया। घटना सामने आते ही जेल प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

4 कैदी हुए गिरफ्तार

शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस फरारी में किसी जेल कर्मचारी की लापरवाही या अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं थी। जानकारी के मुताबिक, कैदियों से भरी वैन को जब जांच के लिए रोका गया, तो उसी वक्त कैदियों में पुलिस अधिकारियों की आंखों में मिर्ची फेंक दी और फरार हो गए। जिसके बाद से तुरंत सभी को ढुंढने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, इस दौरान 14 में से 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी 10 की तलाश जारी है।

बिजनेस वर्ल्ड

सेमीकंडक्टर मिशन पर सरकार खर्च करेगी 1.25 लाख करोड़ रुपए

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मंजूरी आईएसएम 1.0 के लिए निर्धारित किए गए 76,000 करोड़ रुपए के आवंटन से काफी अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, व्यय वित्त समिति ने आईएसएम 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है और अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। फरवरी में पेश किए गए बजट में देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए थे। इसमें कई उपायों के साथ-साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी, जिसका मुख्य मकसद देश में चिप विनिर्माण परिवेश को बढ़ावा देना था। इसमें उपकरण, सामग्री, स्वदेशी डिजाइन और अन्य संबंधित कलपुर्जे शामिल हैं। सरकार का कहना है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप विनिर्माण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत देश में ही चिप डिजाइन, उत्पादन आदि बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई, दो कंपाउंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई और नौ पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अब केवल सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे जमीन पर भी आकार ले रहा है।

रील बनाने वालों की कमाई पर बड़ा संकट, काम के बाद भी नहीं मिल रहा पैसा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

हम और आप रोज अपने फोन पर जिन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर मनोरंजन करते हैं, उनके पीछे की दुनिया में इस वक्त एक बड़ा आर्थिक संकट पनप रहा है। भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बाजार इस साल 5,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूने जा रहा है। लेकिन इस चमकदार तरक्की के पीछे भुगतान में महीनों की देरी, बिना कागजी कार्रवाई के होने वाले सौदे, और धड़ाधड़ खुलती नई एजेंसियों की भीड़ ने एक खतरनाक दबाव पैदा कर दिया है। हालात ये हैं कि वीडियो बनाने वाले छोटे क्रिएटर्स और मार्केटिंग कंपनियों, दोनों के लिए मुनाफा कमाना और टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन इसके काम करने का तरीका आज भी काफी असंगठित है। मशहूर फूड क्रिएटर आयुष सापरा बताते हैं कि आज के दौर में ब्रांड्स या एजेंसियों पर आंख मूंदकर भरोसा करना नामुमकिन सा हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी पैसे मिलने को लेकर है। बड़े और स्थापित क्रिएटर्स अपनी शर्तों पर काम कर लेते हैं, लेकिन छोटे इन्फ्लुएंसर्स के हाथ बंधे होते हैं। बाजार में क्रिएटर्स की भारी भीड़ होने का फायदा उठाते हुए एजेंसियां उन पर वीडियो पब्लिश होने के 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय के बाद पेमेंट लेने का दबाव बनाती हैं। डिजिटल दुनिया में करोड़ों का काम महज अनौपचारिक बातचीत के भरोसे चल रहा है। कई बार ब्रांड्स बिना किसी औपचारिक एग्रीमेंट या ईमेल के सीधे व्हाट्सएप मैसेज या फोन कॉल पर डील पक्की करना चाहते हैं। सापरा कहते हैं कि वे ऐसे प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं, लेकिन छोटे क्रिएटर्स मजबूरी में हामी भर देते हैं। उनके पास काम छोड़ने का विकल्प नहीं होता। किसी भी तरह के लिखित अनुबंध के अभाव में पैसे मारे जाने का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है। इस पूरी परेशानी की जड़ केवल नीयत नहीं, बल्कि बाजार का बुनियादी ढांचा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ओप्रा के सह-संस्थापक प्रणव पानपालिया के मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती वर्किंग कैपिटल (नकद पूंजी) की है। एजेंसियां चाहती हैं कि क्रिएटर्स को तुरंत पैसा दें, लेकिन क्लाइंट भुगतान में लंबा समय लेते हैं।

देश पर बढ़ा विदेशी कर्ज, 72 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा; आम आदमी पर क्या असर?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय इकोनॉमी काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच आरबीआई के ताजा आंकड़ों ने भारत के ऊपर कर्ज की नई तस्वीर पेश की है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देश का कुल विदेशी कर्ज 762.8 अरब डॉलर यानी करीब 72.15 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। मार्च 2026 तक भारत के विदेशी कर्ज में एक साल पहले के मुकाबले 26.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। हालांकि, भारत पर बढ़ते कर्ज का आंकड़ा इससे भी बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की माने तो भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत अमेरिकी डॉलर ने विदेशी कर्ज की वास्तविक बढ़ोतरी को आशंकि रूप से छिपा दिया। अगल वैल्यूएशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है तो विदेशी कर्ज में सिर्फ 26.3 अरब डॉलर नहीं, बल्कि 51 अरब डॉलर की होगी। गौरतलब ही कि किसी भी देश के लिए सिर्फ कर्ज के आंकड़े मायने नहीं रखते, यहां यह भी देखा जाता है कि उसकी इकोनॉमी के मुकाबले कर्ज कितना है। इसी पैमाने पर देखें तो भारत का विदेशी कर्ज जीडीपी के अनुपात से बढ़कर 20.8 प्रतिशत पहुंच गया है, जो एक साल पहले 19.8 प्रतिशत था। यानी आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशी कर्ज में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन, राहत की बात यह है कि ये अनुपात अभी भी कई उभरती और विकसति अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले नियंत्रित दायरे में माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी जानकारी सामने आई है कि सरकार का विदेशी कर्ज कम हुआ है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की विदेशी उधारी में इजाफा हुआ है। नॉन-फाइनेंशियल कॉरपोरेट कंपनियां अकेले कुल विदेशी कर्ज का 36.4 प्रतिशत हिस्सा रखती है। विदेशी बाजारों से अपेक्षाकृत सस्ता फंड जुटाने की वजह से कंपनिया बाहरी उधार का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। विदेशी कर्ज में इजाफा का मतलब यह नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था की संकट की ओर बढ़ रही है। हालांकि, यह एक ऐसा संकेत है जिस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर अमेरीकी मुद्रा मजबूत होती है तो वैश्विक ब्याज दरें हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं या विदेशी बाजारों से पैसा लेना काफी महंगा हो जाता है। इस स्थिति में कंपनियों की ऑपरेशनल लागत बढ़ जाता है। लंबे समय के लिए यही दबाव निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

चीन और पश्चिम को छोड़ भारत के डीपीआई मॉडल का दीवाना हुआ इंडोनेशिया

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में होने वाली जकार्ता यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं होगी, बल्कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की डिजिटल कूटनीति का एक नया इतिहास रचेगी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इंडोनेशिया, अब अपनी भविष्य की डिजिटल नींव भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर रख रहा है। 28 करोड़ की आबादी और लगभग 5 प्रतिशत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि के साथ इंडोनेशिया भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2030 तक इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल ई-कॉमर्स में ही 194.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रणनीतिक रूप से, इंडोनेशिया ने चीन के विनिर्माण और अमेरिका के भू-राजनीतिक संतुलन के बीच भारत को अपने डिजिटल पार्टनर के रूप में चुना है। यह भारत के लिए पिछले एक दशक की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क है। यह भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से प्रेरित है और बेकन 2.0 प्रोटोकॉल पर आधारित है। 7 जुलाई को होने वाले मोदी-प्रबोवो शिखर सम्मेलन के दौरान आयन के पहले लाइव ट्रांजैक्शन की उम्मीद की जा रही है। यह नेटवर्क खरीदारों, विक्रेताओं, रसद प्रदाताओं और भुगतान प्रणालियों को एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ देगा। वर्तमान में इंडोनेशिया में प्लेटफॉर्म कमीशन 25 से 40 प्रतिशत तक है, जिसे आयन के माध्यम से घटाकर 8 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इंडोनेशिया में वर्तमान में 6.5 करोड़ सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 25 से 40 प्रतिशत तक का भारी कमीशन देना पड़ता है। आयन के जरिए इस खर्च को घटाकर 8 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है, जिससे छोटे व्यापारियों का लोकतंत्रीकरण होगा। भारत के यूपीआई और इंडोनेशिया के क्यूआरआईएस भुगतान प्रणाली का एकीकरण इस डिजिटल कॉरिडोर का दूसरा मुख्य स्तंभ है। 2025 के अंत तक क्यूआरआईएस के पास 5.9 करोड़ उपयोगकर्ता और 4.2 करोड़ मर्चेंट थे, जो इसके मूल लक्ष्य से दोगुने से भी अधिक है।

पुतिन के मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन, 12 की मौत

रूस ने औद्योगिक शहरों को बनाया निशाना

हिंदमाता नेटवर्क @ मॉस्को

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। हाल के हुए हमलों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने से न केवल यूक्रेन में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है, बल्कि रूस के भीतर भी ईंधन संकट पैदा हो गया है।

यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का तांडव

रूस की ओर से सोमवार को किए गए भीषण हवाई हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया। ये हमले उस समय हुए जब लोग अपने घरों से बाहर खुले स्थानों पर मौजूद थे, जिसके कारण हताहतों की संख्या काफी अधिक रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि मलबे और गंभीर रूप से घायलों की स्थिति को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। सबसे दर्दनाक मंजर यूक्रेन के निप्रो शहर में देखने को मिला, जहां एक रूसी मिसाइल सीधे एक मिनी बस से जा टकराई। इस हमले में 6 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा, यूक्रेन के नियंत्रण वाले जपोरीजिया क्षेत्र में भी रूसी हमलों ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि खार्कीव में एक युवती की मौत और 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।

रूस के भीतर तेल का अकाल

यूक्रेन ने भी इस युद्ध में अपनी रणनीति बदलते हुए रूस के आर्थिक और ऊर्जा केंद्रों पर सीधा प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस की कई बड़ी रिफायनरियों, तेल-गैस गोदामों और प्रमुख पाइपलाइनों को निशाना बनाया है। इन सटीक हमलों का परिणाम यह हुआ है कि रूस की राजधानी मास्को सहित देश के दक्षिणी हिस्सों और रूसी नियंत्रण वाले क्रीमिया में पेट्रोलियम पदार्थों का गंभीर संकट पैदा हो गया है। रूसी अधिकारियों को मजबूरन इन क्षेत्रों में ईंधन की बिक्री को सीमित करना पड़ा है। यूक्रेन के इन हमलों ने न केवल रूस की घरेलू आपूर्ति व्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि उसके अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस निर्यात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है।

साउथ अफ्रीका में लाठी लेकर विदेशियों को ढूंढ रही भीड़, 25 हजार ने छोड़ा देश

क्या है 30 जून का डेथ वारंट?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

दक्षिण अफ्रीका इस समय एक भीषण मानवीय और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में विदेशी नागरिकों के खिलाफ नफरत और हिंसा की आग भड़क उठी है। स्थानीय कट्टरपंथी समूहों ने बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 30 जून की समय सीमा दी थी, जिसके खत्म होने से पहले ही अब तक लगभग 25,000 प्रवासी डर के मारे देश छोड़कर भाग चुके हैं।

क्यों निशाने पर हैं विदेशी नागरिक?

इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के पारंपरिक जुलु परिधान पहने लोग कर रहे हैं। इन समूहों का दावा है कि विदेशी प्रवासियों के कारण देश में अपराध बढ़ रहा है और वे स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका इस समय लगभग 33 प्रतिशत की भारी बेरोजगारी दर और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिसका गुस्सा अब प्रवासियों पर उतारा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ब्लैक-ऑन-ब्लैक हिंसा का एक नया रूप है, जहां संसाधनों की कमी के कारण अश्वेत ही अश्वेत के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

सड़कों पर लाठी-डंडों के साथ उतरी भीड़

राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग हाथों में लाठी और ढाल लेकर विदेशी नागरिकों की तलाश कर रहे हैं। कई जगहों पर आम लोग स्वयं ही विदेशियों के कागजात जांचने और उन्हें घर या कार्यस्थल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि हाल ही में मोजाम्बिक के दो और मलावी के एक नागरिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। डर के मारे हजारों लोग अस्थाई राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं।

राजनीति और अफवाहों का खेल

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तनाव के पीछे आगामी नगर-निगम चुनाव और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की अवसरवादिता है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक न्यूज और गलत जानकारी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि देश में प्रवासियों की संख्या कुल आबादी का मात्र 5.1 प्रतिशत (लगभग 30 लाख) है, लेकिन उन्हें आर्थिक संकट का बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

फीफा के बीच बांग्लादेश में हर तरफ 'कलमा' लिखे झंडे

भारत के लिए नई टेंशन?

हिंदमाता नेटवर्क @ ढाका

बांग्लादेश में फीफा वर्ल्ड कप के बीच छतों और खंभों पर ब्राजील और अर्जेंटीना के झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन इस फुटबॉल खुमारी के बीच, सड़कों और रिहायशी इलाकों में अचानक काले और सफेद रंग के 'कलमा' लिखे झंडे दिखाई देने लगे हैं। इन झंडों पर अरबी भाषा में 'ला इलाहा इल्लल्लाह' लिखा है। सोशल मीडिया पर इन झंडों के साथ मोटरसाइकिल रैलियों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। इन झंडों के दिखने से बांग्लादेश और पड़ोसी देश भारत में चिंता बढ़ गई है। इसे बांग्लादेश में विदेशी चरमपंथी गुटों के बढ़ते पैर पसारने का संकेत बताया जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ये झंडे सबसे पहले 17 जून 2026 को ढाका के एक फ्लाईओवर पर देखे गए थे। इसके बाद मीरपुर, चटगांव, कॉक्स बाजार और फरीदपुर में भी ऐसे झंडे दिखे।

दो तरह के 'कलमा' वाले झंडे वायरल

देखे गए झंडों में दो रंग हैं। एक सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से लिखा झंडा है, जो तालिबान का है। दूसरा काले बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखा झंडा है, जिसका इस्तेमाल अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और हिज्ब उत-तहरीर जैसे आतंकी संगठन करते हैं। हिज्ब उत-तहरीर पर 2009 में शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 2024 की अशांति के बाद इसने अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। पिछले साल इसने ढाका की मुख्य मस्जिद के सामने 'खिलाफत मार्च' निकाला था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग जुटे थे।

'तौहीदी जनता' का बैनर

इन रैलियों में शामिल कुछ लोग खुद को 'तौहीदी जनता' का हिस्सा बता रहे हैं। ये एक इस्लामी संगठन है। दिलचस्प बात ये है कि एक जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा भी देखा गया। पिछले साल 'तौहीदी जनता' से जुड़े ग्रुप्स पर बांग्लादेश में सूफी संतों की दरगाहों और बाउल गायकों के जमावड़े पर हमले करने के आरोप लगे थे। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने भी हाल ही में चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमास की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जगजाहिर है, लेकिन विदेशी जिहादी विमर्श को जगह देना चिंता की बात है।

फुटबॉल के खिलाफ 'धार्मिक' प्रचार

पिछले कुछ दिनों से ये झंडे फेसबुक और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर भी बिक रहे हैं। दिनाजपुर में एक रैली के आयोजक मुफ्ती अबू बकर सिद्दीकी ने मीडिया से कहा, 'हम लोगों के दिलों में कलमा बसाना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप के उन्माद से दूर रहें।'

कुछ दिन पहले तक एंटी इंडिया नारे लगा रहे थे, अब वीजा के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे हैं बांग्लादेशी

हिंदमाता नेटवर्क @ ढाका

भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्ते धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला, जब भारत ने लगभग दो साल के निलंबन के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर किया। बांग्लादेशी नागरिक कुछ दिन पहले तक सड़कों पर 'एंटी इंडिया' के नारे लग रहे थे, लेकिन अब वही बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पर्यटक वीजा के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से पिछले लगभग दो सालों से निलंबित चल रही अपनी पर्यटक वीजा सेवा को बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दोबारा बहाल कर दिया है। इस सेवा के तहत रविवार यानी 28 जून से बांग्लादेश भर के पांच भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (आईवीएसी) पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जबकि भरे हुए आवेदनों को जमा करने का काम सोमवार यानी 29 जून से शुरू हुआ।

सेंटरों के बाहर उत्सव जैसा माहौल

पहले ही दिन ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में आईवीएसी सेंटर पर सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल था। लंबे वक्त तक सेवा बंद रहने के बाद इसके फिर से शुरू होने पर आवेदकों और पर्यटकों में काफी उत्साह और राहत देखी गई। हालांकि, कुछ वक्त पहले भारत आए बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार जाहेद उर रहमान को सुरक्षा ब्लैकलिस्ट के चलते नई दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया था। इसके बाद वह वापस ढाका लौट गए। इस पर बांग्लादेश में आपत्ति जताई थी।

पांच बड़े शहरों ने सेवाएं शुरू

सूत्रों के मुताबिक, टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन शुरू में पांच बड़े शहरों- ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही, सिलहट और खुलना में आईवीएसी सेंटर्स पर स्वीकार किए जा रहे हैं। धीरे-धीरे इस सेवा का विस्तार दूसरे शहरों के सेंटर्स तक भी किया जाएगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने सीमा पर सुरक्षाबलों और पुलिस ने बॉर्डर पर होने वाली आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है।

हिंदमाता एंकर जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी

काट दूंगा उन हाथों को... पानी नहीं मिलने से छटपटा रहा पाकिस्तान, भारत को दी धमकी

हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की, तो हम उन हाथों को काट देंगे। भारत ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर रखा है। मुसद्दिक मलिक ने सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वह पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और किसी को भी उसका पानी रोकने नहीं देगा।

सिंधु जल संधि लागू होने का दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह लागू है। उनके मुताबिक, भारत इस संधि को न तो अकेले खत्म कर सकता है, न ही इसमें बदलाव कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है और भारत की दलील को किसी वैश्विक मंच पर स्वीकार नहीं किया गया। तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी कह चुके हैं कि पानी हमारी लाइफलाइन भी है और हमारी रेडलाइन भी। तरार कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के जल अधिकार सुरक्षित हैं। पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया कि वह मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करेगा। इसमें कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और कई विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

1960 में लागू हुई थी संधि

सिंधु जल संधि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत के हिस्से में है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को मिलता है। यह संधि कई युद्धों और दोनों देशों के बीच लंबे तनाव के बावजूद लागू रही। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को स्थगित कर दिया। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ, तो वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

भारत ने क्या लिया फैसला?

मंत्री के भड़काऊ बयान के बीच पाकिस्तान खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश में जुटा है। आसान भाषा में समझें तो भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी नहीं रोका है। असलियत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया है। नदी के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। संदेश एक दूसरे को भेजे जाते थे। जल प्रवाह, बांधों, परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर लगातार संपर्क होता था। अब भारत ने इसी सपोर्ट पर रोक लगा रखी है।

दैनिक ठाणे, बुधवार 1 जुलाई, 2026

हिंदमाता मिरर

पैनी नजर, पुख्ता खबर

सुनील गावस्कर ने पूछे तीखे सवाल

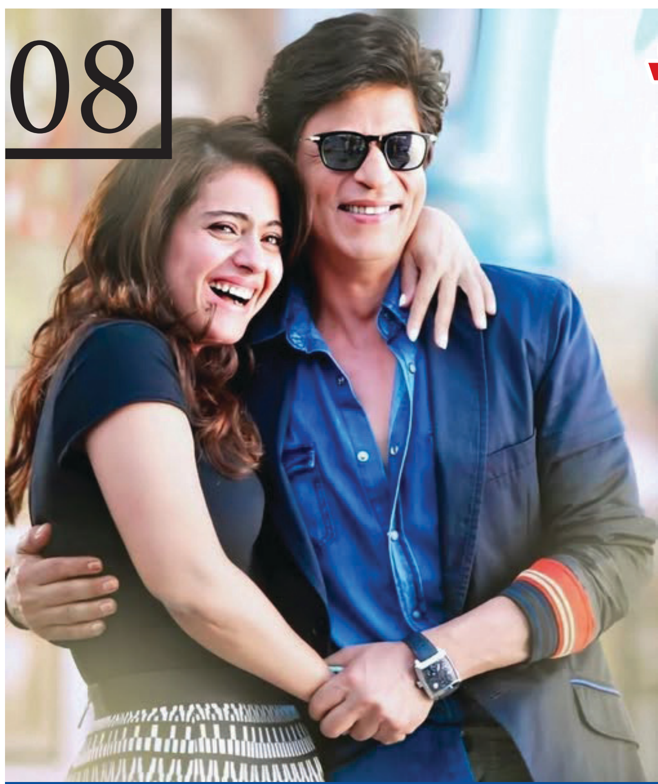

कैसा अजीब सा हीरो है, इसे कहां से लाए होः काजोल

जब भी ऑन-स्क्रीन की बेस्ट जोड़ियों की बात की जाती है तो सबसे पहले काजोल और शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेस्ट जोड़ियों में से एक थीं। जब-जब दोनों साथ में फिल्में करते हैं, वो हमेशा ही हिट जाती हैं। 1993 में दोनों ने सबसे पहले बाजीगर फिल्म में काम किया था और सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये शायद कम लोगों को ही पता है, तो चलिए जानते हैं।

ये कैसा लड़का है ?

- जब काजोल पहली बार शाहरुख खान से मिली थी तो उनका रिएक्शन बहुत अजीब था। वो उन्हें देखकर काफी हैरान रह गईं थी और कहा था, ये कैसा हीरो है, इसे कहां से लेकर आए हो ?
- पहली मुलाकात में काजोल को शाहरुख खान बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। आप की अदालत में एक काजोल ने खुद कहा था कि, मैं पहली बार शाहरुख को देखकर हैरान रह गई थी और कहा था हाय राम कैसा लड़का है ये ?
- इसी के साथ उन्होंने आगे बताया कि उस समय मैं अपने मेकअप मैन से मराठी में बातें करने लग गई कि, इसे कहा से उठाकर लाए हो ? कौन है ये लड़का जो अजीब सा चश्मा पहनकर बैठा हुआ है और वो भी इतनी देर से।

शाहरुख खान का चुप बैठना नहीं था काजोल को पसंद

इसके बाद काजोल ने बताया कि मैं हमेशा से ही बहुत बातें करती हूं और इधर-उधर घूम रही थी लेकिन शाहरुख चुप-चाप बिना बोले, एक ही जगह बैठे हुए थे। उनका यूं शांत बैठना काजोल को बिलकुल पसंद नहीं आया था।

भूमि पेडणेकर ने की पुष्कर यात्रा

अभिनेत्री भूमि पेडणेकर ने हाल ही में राजस्थान के पवित्र शहर पुष्कर की यात्रा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा के गहरे और भावुक अनुभव को फैंस के साथ साझा किया है।

भूमि ने साझा की पुष्कर यात्रा की तस्वीरें

भूमि ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुष्कर यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। भूमि ने बताया कि पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, पुरानी कहानियां और आस्था एक साथ मिलकर दिल को छू लेती हैं। इस यात्रा के दौरान भूमि को वहां के पवित्र मंदिरों और घाटों पर बहुत सुकून मिला।

ब्रह्मा नगरी में हुआ अध्यात्म का अनुभव

भूमि ने पुष्कर के वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि हम सब भगवान ब्रह्मा की सुंदर रचना हैं। पुष्कर घूमते हुए मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था। इस शहर में 1100 से ज्यादा मंदिर हैं और यह भगवान ब्रह्मा का मुख्य तीर्थ स्थल है। यहां की कहानियों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए।

पशु आश्रय गृह ने जीता दिल

मंदिरों के दर्शन करने के अलावा भूमि वहां की एक जानवरों की संस्था गईं। इस यात्रा ने उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी। इस संस्था में उन बेसहारा और घायल जानवरों की देखभाल की जाती है, जिन्हें किसी हादसे या क्रूरता का सामना करना पड़ा हो। इस संस्था में लकवाग्रस्त गायों, पक्षियों, बत्तखों, बंदरों और कई जीवों को बड़े प्यार और सम्मान से रखा जाता है। भूमि ने लिखा कि इन बेजुबानों की सेवा को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि सेवा ही पूजा का सबसे सच्चा रूप है।

परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल

भूमि ने पुष्कर के खाने-पीने और संस्कृति की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि पुष्कर में जहां एक तरफ पारंपरिक और मशहूर मालपुए मिलते हैं। वहीं यहां पर दुनिया भर की संस्कृति को समेटे हुए इजराइली कैफे भी हैं।

‘इक्का’ का दमदार ट्रेलर रिलीज

सनी देओल और अक्षय खन्ना पहली बार नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इक्का’ में साथ नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें कोर्टरूम ड्रामा, पारिवारिक रिश्तों और न्याय की लड़ाई की झलक देखने को मिलती है। सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ट्रेलर में सनी देओल एक सिद्धांतवादी वकील अर्जुन मेहरा के किरदार में दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें हाई-प्रोफाइल हत्या के प्रयास के मामले में शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना) का बचाव करना पड़ता है, तो उनके सिद्धांत और निजी जिंदगी दोनों कठिन परीक्षा से गुजरते हैं।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने उज्जैन महाकाल में किए दर्शन

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति, राजनेता राघव चड्ढा ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन किए। दोनों ने यहां भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया।

रिणीति ने साझा किया वीडियो

परिणीति ने इस आध्यात्मिक यात्रा का एक खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इस वीडियो में परिणीति पीच रंग की पारंपरिक साड़ी में सिर ढके हुए नजर आ रही हैं। वहीं राघव चड्ढा पारंपरिक पोशाक के साथ केसरिया शॉल ओढ़े हुए हैं। दोनों मंदिर के पुजारियों के साथ पूरे भक्ति भाव से बैठकर प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं।

शिव स्तुति को मिला फैंस का प्यार

इस वीडियो के साथ परिणीति ने अपने फैंस के लिए एक बेहद निजी और खास बात साझा की। उन्होंने बताया कि जब वह गर्भवती थीं, तब एक शांत सुबह उन्होंने एक ‘शिव स्तुति’ रिकॉर्ड की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को यह इतनी पसंद आएगी।

शिव स्तुति बनी सुबह की प्लेलिस्ट का हिस्सा

परिणीति ने लिखा कि मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान एक सुबह इस शिव स्तुति को रिकॉर्ड किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसे इतना प्यार मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है कि यह स्तुति अब आप लोगों की सुबह की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे कई साल से यह हमारे परिवार की प्लेलिस्ट में शामिल थी।

मुंबई छोड़ बेंगलुरु पहुंचे हार्दिक पांड्या

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने करियर को लेकर बड़ा फैसला किया है। पांड्या अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। अभी तक वह मुंबई में रहा करते थे, लेकिन अब बेंगुलरु में रहेंगे। पांड्या ने ये फैसला अपने करियर को देखते हुए लिया है। दरअसल, बेंगलुरु में बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) है। ये वो संस्था है जहां खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं और टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी चोट पर काम करने के लिए यहां आते हैं। पांड्या भी अब यहीं ट्रेनिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, पांड्या ने सीओई को अपना परमानेंट ट्रेनिंग बेस बनाने का फैसला किया है।

पांड्या ने लिया अलग फैसला

पांड्या के इस फैसले को काफी अलग माना जा रहा है क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया है। पांड्या अपना ट्रेनिंग बेस बेंगलुरु शिफ्ट करने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर हैं। पूर्व में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के तौर पर मशहूर इस संस्था में यूं तो क्रिकेटर अपनी चोटों पर काम करने, फिटनेस या फिर नेशनल कैम्प में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। कोई भी क्रिकेटर यहां स्थायी रूप से ट्रेनिंग के लिए नहीं आता था। पांड्या यूं तो गुजरात के बड़ौदा से हैं, लेकिन वह कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। वह घनसोली स्थित अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की अकादमी में ट्रेनिंग किया करते थे।

चोट से जूझ रहे हैं पांड्या

पांड्या इस समय अपनी चोट से परेशान हैं। उन्हें क्वाड्रीसेप्स इंजुरी हुई है। इसी कारण वह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे। वह सीओई में ही अपनी चोट पर काम कर रहे थे। देखा जाए तो पांड्या ने अपने बीते तकरीबन छह महीने बेंगलुरु में सीओई में ही बिताए हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि हार्दिक पहले से ही बेंगलुरू में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने शहर से बाहर एक प्रॉपर्टी किराए पर ली है जो सीओई के पास है। वह सीओई को अपना परमानेंट ट्रेनिंग बेस बनाने वाले पहले बड़े क्रिकेटर होंगे। उन्होंने कहा कि हार्दिक मुंबई से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उनको अपने लोअर पार्ले स्थित घर से ट्रेनिंग के लिए जाना काफी परेशानी बन रहा था। वह केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी हैं और इसलिए वह सीओई में हर चीज का उपयोग कर सकते हैं।

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ में वीर हिरानी के साथ काम कर भावुक हुए अरशद वारसी

राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी अपनी पहली वेब सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। सीरीज के ट्रेलर में उनकी दमदार झलक देखने को मिली है, जहां वह अरशद वारसी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि अरशद और वीर इससे पहले फिल्म ‘मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.’ में भी साथ नजर आ चुके हैं, जब वीर चाइल्ड आर्टिस्ट थे। अब वर्षों बाद दोनों का फिर साथ आना अरशद के लिए एक भावुक और खास पल बन गया है।

वीर एक स्ट्रेस-फ्री और शानदार एक्टर है

एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने वीर हिरानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वीर न सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता भी हैं जिनके साथ काम करना बेहद आसान है। अरशद ने कहा कि वो जैसा इंसान है, उसी वजह से लोग उसे बार-बार अपनी फिल्मों में लेना चाहेंगे। वह बिना किसी नखरे के काम करने वाला स्ट्रेस-फ्री एक्टर है। जब भी उसे मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं दिल से चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट उसके लिए बड़ी सफलता साबित हो।

वो मेरे बेटे जैसा है, बोले अरशद वारसी

अरशद ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने वीर को बचपन से बड़ा होते देखा है और आज उनके साथ काम करना बेहद खास एहसास है। उन्होंने कहा कि वीर मेरे लिए बेटे जैसा है। कभी वह छोटा-सा बच्चा था, जिसे मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए भेजा गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों साथ काम करेंगे। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना बेटा मेरे साथ काम कर रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि वीर ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में शानदार काम किया है और उनमें एक सफल अभिनेता बनने के लिए जरूरी सभी गुण मौजूद हैं।

अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारना था और यह उनके लिए बेहद मुश्किल था

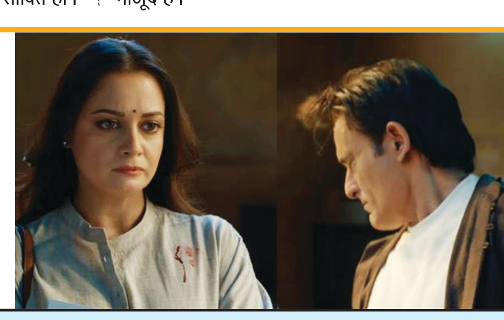

जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दीया मिर्जा, सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म इक्का आने वाली है। हाल ही में 29 जून को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। बॉलीवुड में पहली बार दिया मिर्जा और अक्षय खन्ना पहली बार एक साथ काम करने जा रहे हैं। मुंबई में इस फिल्म के ट्रेलर को लांच किया गया और इस समय पर इस फिल्म की सारी स्टार-कास्ट मौजूद थी। इस दौरान बात करते हुए दिया ने अपना एक किस्सा शेयर किया, उन्होंने बताया कि अक्षय खन्ना के साथ शूटिंग करने में बहुत परेशानी हुई। ऐसा इस वजह से क्योंकि उनको अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारना था और यह उनके लिए बेहद मुश्किल था।

क्या भारत ने फिट की जगह चोटिल खिलाड़ियों पर जताया भरोसा?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत का सफर ग्रुप चरण में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में हार के बाद टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत की असली हार ऑस्ट्रेलिया से नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली थी। उन्होंने टीम की खराब फील्डिंग, रणनीति और खिलाड़ियों की फिटनेस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भी जांचने की जरूरत है कि क्या भारत ने पूरी तरह फिट खिलाड़ियों को ही मैदान में उतारा था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार बनी टर्निंग पॉइंट

गावस्कर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से हार कोई बड़ा उलटफेर नहीं था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने भारत का अभियान लगभग वहीं खत्म कर दिया था। उन्होंने स्पोर्टस्टार के लिए लिखे अपने कॉलम में कहा कि भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया से हारना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था, लेकिन इससे दिन बेहतर भी नहीं हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका को हराना चाहिए था, लेकिन उस मैच में फील्डिंग इतनी खराब रही कि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद टीम हार गई और उसी हार ने उन्हें लगभग टूनार्मेंट से बाहर कर दिया।

क्या भारत ने पूरी तरह फिट खिलाड़ियों को नहीं खेलाया?

गावस्कर ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि दूर से टिप्पणी करना आसान नहीं है, लेकिन मैदान पर कुछ खिलाड़ियों के हाथों में बंधी पट्टियां देखकर ऐसा लगा कि शायद सभी खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं थे। उन्होंने लिखा कि दूर से टिप्पणी करना आसान नहीं है, हर क्रिकेट प्रेमी के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या हमने पूरी तरह फिट खिलाड़ियों को खिलाया था या कुछ खिलाड़ी सौ प्रतिशत फिट नहीं थे? अगर कोई मैच जिताने वाला खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं है, तब उसे खिलाना समझ में आता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिजर्व खिलाड़ी उसकी जगह लेने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। उम्मीद है कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन खिलाड़ियों को उंगलियों पर पट्टी बांधकर खेलते देख ऐसा जरूर लगा कि वे किसी न किसी चोट से जूझ रहे थे, भले ही वह मामूली ही क्यों न हो।

रणनीति पर भी उठाए सवाल

गावस्कर ने भारतीय टीम की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए। विरोधी बल्लेबाज लगातार स्पिनरों के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रन बना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने उस क्षेत्र में फील्डर लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लिखा कि एक और बात साफ नजर आई कि वनडे जीत और अन्य मुकाबलों के बावजूद स्पिनरों के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगातार रन बनाए जा रहे थे। इसके बावजूद उस क्षेत्र को फील्डर से नहीं भरा गया और बल्लेबाजों को खुले बल्ले से हवा में शॉट खेलने के लिए मजबूर करने की कोई कोशिश नहीं हुई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार से टूटा सपना

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की 27 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की उपयोगी शुरुआत की बदौलत 170/4 का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 72/3 के स्कोर से शानदार वापसी की। एलिस पेरी और एशले गार्डनर के बीच 100 रन की साझेदारी ने मैच भारत की पकड़ से छीन लिया और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

कंगना रनौत ने पूरी की अगली फिल्म की शूटिंग

कंगना रनौत अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर सकी। इस बीच उनकी अपकमिंग फिल्म ‘क्वीन 2’ को लेकर नई अपडेट आई है। खबर है कि कंगना ने अपनी मशहूर फिल्म ‘क्वीन’ के बहुप्रतीक्षित सीक्वल ‘क्वीन 2’ की शूटिंग पूरी कर ली है।

कंगना ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एक्टर-फिल्ममेकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर यह जानकारी दी। उन्होंने कास्ट और क्रू के साथ शूटिंग खत्म होने का जश्न मनाते हुए एक फोटो शेयर की। फोटो में रनौत को फिल्म की टीम के साथ देखा गया। शूटिंग पूरी होने के साथ ही, यह प्रोजेक्ट अब पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है।

कब रिलीज हुई ‘क्वीन’?

मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट का एलान नहीं किया है। ‘क्वीन 2’ में कंगना रनौत के मशहूर किरदार 'रानी' की वापसी हो रही है। दर्शकों ने फिल्म ‘क्वीन’ को काफी प्यार दिया था। 2014 में रिलीज हुई ओरिजिनल ‘क्वीन’ का निर्देशन विकास बहल ने किया था और इसे समीक्षकों से खूब तारीफ मिली थी।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में कंगना रनौत ने रानी मेहरा का किरदार निभाया था। रानी दिल्ली की एक ऐसी लड़की थी, जिसे हमेशा घर की चारदीवारी में रखा गया था। जब उसका मंगेतर (राजकुमार राव) शादी तोड़ देता है, तो वह अकेले ही हनीमून पर निकल पड़ती है। यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान, रानी का आत्मविश्वास बढ़ता है, वह आजादी को अपनाती है और खुद को नए सिरे से खोजती है। इसे अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना ने प्रोड्यूस किया था।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित। दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक:** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com** RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 **स्थानीय संपादक:** शिवप्रताप